गैरसैंण, गुरूवार
4 जुलाई 2024
वर्षः 16
अंकः 68 पृष्ठः 4
मूल्यः 2.00
RNI No.UTTHIN/2005/16338

जयन्त

निर्भीक – निष्पक्ष – जनसरोकार
www.dainikjayantnews.com
स्थापित 1979
संस्थापक : स्व. नरेन्द्र उनियाल
डाक पंजीयन पी.ए.ओ.07-2024-26 फोन: 9412081969 email: nagendra.uniyal@gmail.com

एक नजर

रोडवेज कर्मचारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी

देहरादून। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद पर्वतीय डिपो शाखा ने मांगों का निराकरण नहीं होने पर आक्रोश जताया। कर्मचारियों ने बुधवार को सहायक महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की चेतावनी दी है। शाखा अध्यक्ष यशपाल शर्मा ने कहा कि 26 जुलाई को ट्रांसपोर्टनगर में कर्मचारियों की बैठक हुई थी। इसमें कर्मचारियों ने वाहन के अनुपात में तकनीकी कर्मचारियों की तैनात करने, एरियर का भुगतान करने, वर्कशॉप में स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति करवाने, बसों की मरम्मत के लिए सुविधाएं जुटाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की। सभी मांगों से प्रबंधन को अवगत करवाया जा चुका था, लेकिन अभी तक मांगें पूरी नहीं हो पाई। चेताया कि यदि जल्द मांगें नहीं मानी गई तो कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

डेंगू, मलेरिया रोकथाम के दिए निर्देश

देहरादून। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक स्वाति भदौरिया ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जल जनित रोग डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया व जापानी इंसेफेलाइटिस की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में बीमारियों से निपटने के लिए दवाई, मच्छरदारी, जांच किट आदि खरीद लिए जाएं। साथ ही उन्होंने लार्वा नष्ट करने के अभियान को भी तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग ब्लॉक स्तर पर समन्वय बनाकर काम करें। स्कूलों में पूरी बाजू की यूनिफार्म लागू की जाए। इस अवसर पर विभाग के अनेक अधिकारी मौजूद रहे।

कालसी–चकराता मोटर मार्ग समेत पांच मार्गों पर यातायात घंटों बंद

विकासनगर। बारिश के कारण क्षेत्र की सड़कों का बंद होने का सिलसिला शुरू हो गया है। मंगलवार दोपहर बंद हुए मार्ग खुलने के बाद बुधवार को भी कालसी–चकराता मोटर मार्ग समेत क्षेत्र के पांच मोटर मार्ग घंटों बंद रहे, जिसके चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। मंगलवार रात और बुधवार सबह से हो रही बारिश के चलते बंद हुए मोटर मार्गों से बड़ी आबादी गांवों में ही फंसी रही। कालसी–चकराता मोटर मार्ग पर असनाड़ी के पास मलबा आने से दोपहर एक बजे यातयात बंद हो गया था, जिसे शाम पांच बजे बहाल किया गया। ग्रामीण मार्गों के बंद होने से किसानों को भी अपनी नगदी फसलों को मंडी तक पहुंचाने में विलंब हुआ। वहीं सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जेसीबी से मार्गों को खोलने में दिक्कत आ रही है। जनपद आपदा प्रबंधन द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार बारिश के बाद मलबा आ जाने से अस्थायी खंड लोक निर्माण विभाग चकराता के चकराता–खारसी मोटर मार्ग, सुनोई से पेनुवा मोटर मार्ग, लोक निर्माण विभाग सहिया के बिजऊ–कुइथा–खतार मोटर मार्ग, पीएमजीएसवाई कालसी का गडोल–सकरोल मोटर मार्ग पर यातायात बाधित रहा। इन सभी मार्गों पर मंगलवार रात 11 बजे से मलबा आना शुरू हो गया था, हालांकि बुधवार सुबह से जेसीबी से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण शाम पांच बजे तक भी बंद मार्गों पर यातायात बहाल नहीं हुआ था।

पर्वतीय इलाके में बारिश के चलते गंगा का जलस्तर घट–बढ़ रहा

देहरादून। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में हो रही बारिश से मैदानी शहरों में भी खतरे की घंटी बजने लगी है। मॉनसूनी बरसात के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पुलिस–प्रशासन की ओर से एहतियात के तौर पर तटीय इलाके में मुनादी कर लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बारिश से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। प्रशासन के मुताबिक बुधवार दोपहर में गंगा चेतावनी बिन्दु 339.50 मीटर से 70 सेंटीमीटर नीचे बह रहीं थीं जबकि शाम करीब चार बजे गंगा का जलस्तर में 40 सेंटीमीटर की गिरावट दर्ज की गई। बुधवार दोपहर अचानक गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी शुरू हो गई। जलस्तर बढ़ने पर तटीय इलाके में घाट जलमग्न हो गये।

जमरानी बांध बहुउद्देशीय और सौंग बांध पेयजल परियोजना पर कार्य जल्द शुरू करें : धामी

शहरों के मास्टर ड्रेनेज प्लान और फ्लड प्लेन जोनिंग के कार्यों में तेजी लाएं

जयन्त प्रतिनिधि।

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में सिंचाई विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि शहरों के मास्टर ड्रेनेज प्लान और फ्लड प्लेन जोनिंग के कार्यों में तेजी लाई जाए। सीएम ने कहा कि जल स्तर बढ़ाने के लिए बांधों से सिल्ट निकालने और ड्रेजिंग सिस्टम के लिए 02 माह के अन्दर ठोस प्लान बनाकर प्रस्तुत किये जाने के साथ पिंडर और कोसी नदी को आपस में जोड़ने के लिए राज्य स्तर पर की जाने वाली सभी कार्यवाही में तेजी लाने लाएं। उन्होंने कहा कि गंगा और उसकी सहायक नदियों में शुद्ध पानी जाए, इसके लिए ऐसे नाले भी चिन्हित किये जाए जहां एसटीपी नहीं लगे हैं। घाटों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ सुरक्षा के कार्यों में तेजी लाई जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा बढ़ाने तथा नहरों के

अनुरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिये कि जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना और सौंग बांध पेयजल परियोजना पर कार्य जल्द शुरू हो, इसके लिए सितम्बर तक सभी कार्यवाही पूर्ण की जाए। जमरानी बांध परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 710 करोड़ रूपये के बजट का प्राविधान किया गया है। इस परियोजना से हल्द्वानी शहर एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में 117 एम.एल.डी पेयजल की उपलब्धता, लगभग 57 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया जायेगा, जबकि सौंग बांध परियोजना से देहरादून शहर एवं उपनगरीय क्षेत्रों के लिए 2053 तक की अनुमानित आबादी के लिए 150 एम.एल.डी. ग्रविटी से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सौंग बांध के लिए 300 करोड़ के बजट का प्राविधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नैनीताल जनपद के बलियानाला भूस्खलन क्षेत्र का उपचार कार्य, चमोली जनपद के हल्दापानी लॉ कॉलेज के निकट भूधसांव और भूस्खलन की रोकथाम के लिए सुरक्षात्मक कार्य और पिथौरागढ़ के धारचूला विकासखण्ड में ग्वालगांव भूस्खलन उपचार के कार्य जल्द पूर्ण किये जाएं। बैठक में जानकारी दी गई कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने, पर्यटन विकास मत्स्य पालन एवं भू जल संवंर्द्धन लिए पिथौरागढ़ में थरकोट झील, चम्पावत में कोलीढ़ेक झाल अल्मोड़ा में गगास नदी पर जलाशय का निर्माण किया गया है। धारचूला में काली नदी पर स्थित घटगाढ़ नाले से भारत-नेपाल पुल तक तटबन्ध सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया है। राज्य के 14 महत्वपूर्ण शहरों में ड्रेनेज प्लान पर कार्य किया जा रहा है, देहरादून का सर्वे पूरा कर लिया गया है। बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, डॉ. आर. राजेश कुमार, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मौसमपूर्वानुमान : उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट

देहरादून। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड में पांच जुलाई तक भारी बारिश के आसार हैं। आईएमडी ने उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में 3 से पांच जुलाई तक तेज हवाओं के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, दक्षिण–पूर्वी पाकिस्तान पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर–पश्चिम और मध्य भारत में गरज–चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिण पश्चिमी मानसून ने भी देश के अधिकांश हिस्सों को कवर कर लिया है। इन वेदर सिस्टम के प्रभाव से उत्तराखंड में मौसम बेहद खराब रहने वाला है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में सात जुलाई तक मौसम बेहद खराब रहेगा। मौसम विभाग ने 3 से लेकर 6 जुलाई तक भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।

आईएमडी का कहना है कि सात जुलाई को भी उत्तराखंड में मौसम कमोबेश भारी बारिश वाला ही रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में सात जुलाई को भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।आईएमडी ने लोगों से फ्लैश फ्लड वाली खतरनाक जगहों से बचने की सलाह दी है। मौसम विभाग के मुताबिक, गंगोत्री और यमुनोत्री में तीन से सात जुलाई के दौरान तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बदरीनाथ और हेमकुंड साहिब में अगले 24 घंटे के दौरान तेज हवाओं के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

यूक्रेन–रूस युद्ध में फंसे भारतीयों को लेकर चिंतित मोदी सरकार

अगले हफ्ते पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की होगी अहम बैठक

नई दिल्ली। भारत ने रूस के समक्ष एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि रूस–यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल के लिए गलत तरीके से ले जाये भारतीयों की स्वदेश वापसी सुनिश्चित होनी चाहिए। कजाकिस्तान में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय वार्ता में इस मुद्दे को उठाया। दोनों विदेश मंत्री कजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए वहां हैं। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अगले हफ्ते मॉस्को में होने वाली भारत–रूस शिखर बैठक के एजेंडे पर भी बात हुई है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की तरफ से भी राष्ट्रपति पुतिन के समक्ष भारतीयों को गलत सूचना के आधार पर रूस की सेना में भर्ती किये जाने का मामला उठाया जाएगा।

रूस–यूक्रेन सीमा पर फंसें है दर्जनों भारतीय

यूक्रेन–रूस सीमा पर दर्जनों भारतीयों के फंसे होने की संभावना है। इनमें से तकरीबन दो दर्जन भारतीयों के परिजनों ने विदेश मंत्रालय से संपर्क किया है और दस भारतीयों को स्वदेश लाने में सरकार सफल भी रही है। जबकि अभी तक यूक्रेन सीमा पर दो भारतीयों के युद्ध में मारे जाने की सूचना है।

युद्ध ग्रस्त इलाकों में फंसे भारतीय लोगों की सुरक्षा पर सरकार का जोर

जयशंकर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि, अस्ताना में विदेश मंत्री लावरोव से मुलाकात हुई। हमारे बीच द्विपक्षीय संबंधों से लेकर समसामयिक वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। युद्ध में फंसे भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा मैंने बहुत ही जोरदार तरीके से उठाया है। मैने उन भारतीयों के सुरक्षित वापसी पर जोर दिया है। दूसरे अन्य मुद्दों पर भी हमारे बीच विचारों का आदान–प्रदान हुआ है।

17 साल बाद मां से मिला बेटा, 9 वर्ष की उम्र में अपहरण कर ले जाया गया था राजस्थान

देहरादून ,17 सालों तक रोज बूढ़ी आखें दरवाजे से बाहर देखती रहती थीं और आखिरकार सालों का लंबा इंतजार खत्म हो गया। जब मां और बेटे की 19 साल के बाद मुलाकात हुई तो दोनों की आंखों से आंसू छलक पड़े। यह हैरान करने वाला मामला देहरादून जिले में सामने आया है। देहरादून से करीब 17 साल पहले अगवा किया गया राजू सोमवार को अपने घर पहुंचा। बच्चे का अपहरण करने वालों ने राजू नाम दिया था। अब इसी नाम से उसकी पहचान हो रही है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि बीते 25 जून को एक युवक पुलिस कार्यालय स्थित एएचटीयू कार्यालय पहुंचा। उसने बताया कि करीब 16–17 वर्ष पहले जब उसकी आयु 9 वर्ष थी तो उसे घर के पास से उठाकर राजस्थान में अनजान जगह पर ले जाया गया था। वहां उससे भेड़–बकरी चराने का काम कराया जा रहा था। उसने बताया वहां से भेड़ लेने गए एक ट्रक ड्राइवर की मदद से वह निकलकर दून पहुंचा है। उसने बताया कि अपहरण के वक्त उसके पिता परचून की दुकान चलाते थे। घर में उसकी मां और चार बहन थी। उसे अपने घर के मोहल्ले की जानकारी नहीं थी। सोमवार को ब्राह्मणवाला निवासी उसकी मां आशा शर्मा ने पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2008 में उनका बेटा घर से गायब हो गया। उसकी काफी तलाश की गई थी। उसका नाम मोनू था। महिला को युवक से मिलाया तो उसने अपनी मां के रूप में पहचान की।

6 साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी को हाईकोर्ट ने किया बरी

पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा

रांची ,झारखंड हाई कोर्ट ने 6 साल की बच्ची से रेप और हत्या के एक मामले में आरोपी को बरी कर दिया है। आरोपी को झारखंड के राजमहल की पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने पाया कि अभियुक्त के खिलाफ अपराध में संलिप्तता के साक्ष्य नहीं हैं।

कोर्ट ने कहा कि सिर्फ अंतिम बार अभियुक्त और पीड़िता (मृतका) का एक साथ देखा जाना दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। यह वारदात साहिबगंज जिले के राजमहल में 4 मार्च, 2015 को हुई थी। छह साल की बच्ची का शव शिमला बहाल पोखर मैदान के पास पाया गया था। उसके कपड़े अस्त–व्यस्त थे और गले में चोट के निशान थे।

परिजनों की शिकायत पर इस मामले में राहत शेख नामक शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एफआईआर के मुताबिक राहत शेख उस रोज शाम पांच बजे बच्ची को अपने कंधे

पर बिठाकर मैदान की तरफ ले जाते देखा गया था। परिजनों ने उसपर बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या का संदेह जताया था।

राजमहल के पोक्सो की विशेष अदालत ने इस मामले में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष के अनुसंधानकर्ता पुलिस अफसर सहित 12 गवाहों का परीक्षण कराया था। कुछ गवाहों का कहना था कि उन्होंने राहत शेख को अपने साथ बच्ची को साथ लेकर शिमला बहाल पोखर मैदान की तरफ ले जाते देखा था।

ट्रायल पूरा होने के बाद पॉक्सो कोर्ट ने राहत शेख को 1 दिसंबर 2022 को दोषी करार दिया और और 12 दिसंबर 2022 को उसे फांसी की सजा सुनाई। इसके बाद राज्य सरकार ने अभियुक्त की फांसी की सजा कन्फर्म करने को लेकर हाई कोर्ट में अपील की थी, तो दूसरी तरफ राहत शेख ने भी पॉक्सो कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी।

अब हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तीन–चार लोगों ने अभियुक्त को उस बच्ची को ले जाते देखा, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर उसे दोषसिद्ध नहीं माना जा सकता। अनुसंधान में घटना का समय एवं मृतका की लाश के मिलने के समय का उल्लेख नहीं है। अभियुक्त और मृतका के परिवार के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे। उनसे कोई दुश्मनी भी नहीं थी। वह प्रतिदिन बच्ची को घुमाने साथ ले जाता था और उसके पास बच्ची की हत्या का कोई उद्देश्य नहीं था।

यूपी में हाथरस हादसे के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट, भीड़ प्रबंधन पर फोकस के दिए गए निर्देश

देहरादून। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ मचने और बड़ी संख्या में लोगों की मौत होने के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट हो गई है। प्रदेश में विभिन्न आयोजनों के दौरान भीड़ प्रबंधन पर पुलिस ने फोकस किया है और इसके लिए कसरत भी की जा रही है। अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था एपी अंशुमान ने समय–समय पर आयोजित होने वाले मेले, धार्मिक आयोजन व अन्य अवसरों पर भीड़ प्रबंधन को लेकर गंभीरता से योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। खासकर आगामी कांवड़ मेले में भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने को कहा है।

अपर पुलिस महानिदेशक ने की बैठक

बुधवार को पुलिस मुख्यालय में अपर पुलिस महानिदेशक ने समस्त परिक्षेत्र, जनपद प्रभारियों, पुलिस महानिरीक्षक,

सुरक्षा, पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था एवं पुलिस अधीक्षक रेलवे के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से बैठक की।

बैठक में उन्होंने भीड़ प्रबंधन के दृष्टिगत जनपदों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को गंभीरता से लिए जाने, आयोजन के लिए एनओसी दिए जाने से पूर्व थाना प्रभारी की ओर से स्वयं मौके पर जाकर आयोजन स्थल की भीड़ क्षमता, प्रवेश–निवासी द्वार, पार्किंग आदि का जायजा लिया जाए। मेले, धार्मिक आयोजन व अन्य कार्यक्रम अनुमति के बाद ही होने दिए जाएं।

आयोजनों के एसओपी तैयार कर पुलिस मुख्यालय उपलब्ध कराने के आदेश

जनपद प्रभारी अपने–अपने जनपदों में होने वाले छोटे–बड़े आयोजनों के संबंध में एसओपी तैयार कर यथाशीघ्र पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराएं। उन्होंने जनपदों में वर्ष में होने वाले समस्त मेले, त्योहारों एवं अन्य अवसरों पर होने वाले कार्यक्रमों का वार्षिक कैलेंडर तैयार कर उसके अनुरूप समय से आवश्यक पुलिस प्रबंध सुनिश्चित किये जाएं।

बिहार में 10 दिन के भीतर पांचवां पुल धराशायी, दो दर्जन से ज्यादा गांवों का आपस में संपर्क टूटा

सीवान , बिहार के सीवान में गंडकी नदी (गंडक नहर) पर बना पुल का एक पिलर नदी में धंस गया, जिससे पुल का एक छोर नदी में ढह गया। यह पुल दारौंदा प्रखंड अंतर्गत देवरिया और भीखा बांध गांव की सीमा पर स्थित है। पुल के जर्जर होने को लेकर आसपास के गांव के लोगों ने बीते 22 जून को विरोध प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद अधिकारियों ने इसकी मरम्मत भी करायी थी। बावजूद इसके बुधवार सुबह करीब 5 बजे पुल का एक पिलर नदी में धंस गया। बता दें कि बिहार में 10 दिन के भीतर पांचवां पुल धराशायी हुआ है। 22 जून के विरोध प्रदर्शन के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने पथ निर्माण विभाग द्वारा सभी पुल का सर्वे कराया था। यह पुल गरौली से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते दिन हुई भारी बारिश के चलते पानी का स्तर बढ़ गया और बहाव तेज होने से पुल धंस गया।

राहुल गांधी पर मंडराया हमले का खतरा, हाई अलर्ट पर पुलिस

नई दिल्ली ,संसद में पिछले दिनों हिंदुओं को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। देश में कई जगह राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन भी किए गए है। वहीं अब राहुल गांधी के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी पर हमले का खतरा बताया गया है। दिल्ली पुलिस को खुफिया विभाग से इनपुट मिला हैं कि हिंदू संगठनों से जुड़े लोग कांग्रेस नेता पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने गृहमंत्रालय के आदेश के बाद राहुल गांधी व उनके आवास की सुरक्षा बढ़ा दी है। आवास पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। साथ ही इलाके में रहने वाले कांग्रेस नेताओं पर नजर रखी जा रही है। नई दिल्ली में खुफिया तंत्र को अलर्ट कर दिया गया है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को हिंदुओं को लेकर बयान दिया था। इसके

बाद दिल्ली पुलिस को देर रात इनपुट मिले कि हिंदू संगठनों से नेता राहुल गांधी पर हमला कर सकते हैं। इन संगठनों के लोग नई दिल्ली इलाके में पोस्टर व बैनर आदि लगा सकते हैं। राहुल गांधी के आवास पर दो प्लाटून फोर्स तैनात की गई है। एक प्लाटून में 16 से 18 पुलिसकर्मी होते हैं। इसके अलावा तुगलक रोड थाने से आठ से 20 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हाथरस मामला

नई दिल्ली। हाथरस भगदड़ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक जनहित याचिका दाखिल हुई है जिसमें कहा गया है कि सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह दो जुलाई की हाथरस भगदड़ की घटना की जांच के लिए तत्काल सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश की निगरानी में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित करे।

दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई

जनहित याचिका में यह भी मांग की गई है कि जन सुरक्षा के हितों को देखते हुए भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों इसके लिए समिति दिशा निर्देश तय करने के सुझाव दे। उत्तर प्रदेश सरकार को हाथरस भगदड़ की स्थिति रिपोर्ट दाखिल का निर्देश दिया जाए साथ ही पूछा जाए कि लापरवाही के दोषियों के खिलाफ

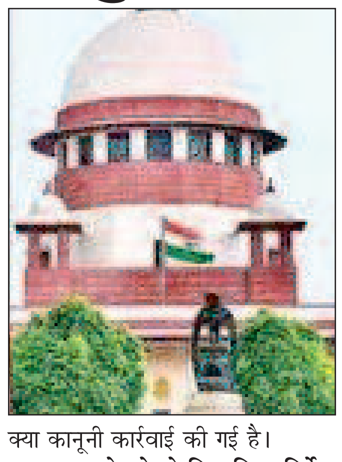

क्या कानूनी कार्रवाई की गई है।

भगदड़ रोकने के लिए दिशा निर्देश

उत्तर प्रदेश के हाथरस में दो जुलाई को सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में सौ से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों अन्य घायल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में वकील विशाल तिवारी ने यह जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि सभी राज्यों को निर्देश दिया जाए कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धार्मिक व अन्य आयोजनों पर भगदड़ रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करें।

पहले की घटनाओं से नहीं लिया सबक

राज्य सरकारें स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर बताएं कि भगदड़ की घटनाओं से निपटने के लिए जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर क्या चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। दाखिल याचिका में पूर्व की भीड़भाड़ वाली जगहों पर हुई भगदड़ की घटनाओं और उसमें हुई मौतें का भी जिक्रकिया गया है।

कंगना रनौत को थप्पड़ जडने वाली कुलविंदर कौर बहाल, चंडीगढ़ से हुआ तबादला

चंडीगढ़ ,। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर को वापस बहाल कर दिया गया है। उनका चंडीगढ़ से बेंगलुरु तबादला कर दिया गया है। साथ ही, उन्हें तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके बाद कुलविंदर को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया था।

बता दें, थप्पड़ कांड के बाद कई किसान संगठनों ने कुलविंदर का समर्थन किया था। इसके अलावा, उनके पूरे परिवार व गांव वाले भी कुलविंदर के समर्थन में आ गए थे और उनके नौकरी से सस्पेंड किए जाने का विरोध जताया था। पुलिस ने कुलविंदर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की थी।

हाथरस हादसा : बाबा के कमांडो की धक्का–मुक्की से मची थी भगदड़, जांच रिपोर्ट में खुलासा

हाथरस ,उत्तर प्रदेश के हाथरस के में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। अब इस हादसे की जांच रिपोर्ट एसडीएम ने अब जिलाधिकारी (डीएम) को सौंपी है। रिपोर्ट के मुताबिक, सत्संग के समापन के बाद भीड़ भोले बाबा के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके सेवादार और निजी सुरक्षाकर्मियों (ब्लैक कमांडो) ने खुद ही धक्का–मुक्की करनी शुरू कर दी। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर भगदड़ मच गई। एसडीएम के मुताबिक, सत्संग में दो लाख से अधिक की भीड़ मौजूद थी। भोले बाबा लगभग दोपहर 12.30 बजे पंडाल में पहुंचे और उनका कार्यक्रम 1 घंटे तक चला। इसी बीच, 1.40 बजे भोले बाबा पंडाल से

निकले, तभी श्रद्धालु उनके चरण की धूल छूने के लिए आगे बढ़े। लोग डिवाइडर से कूद–कूद कर बाबा के वाहन की और दौडऩे लगे। लेकिन बाबा के निजी गाड्र्स और सेवादारों ने खुद ही धक्का–मुक्की करनी शुरू कर दी। इसके बाद कुछ लोग नीचे गिर गए। फिर लोग एक–दूसरे को कुचलने लगे। एसडीएम की रिपोर्ट के मुताबिक,कई श्रद्धालु कार्यक्रम स्थल के सामने खेत की ओर भागे, लेकिन खेत बलुई थी। इस वजह से कई श्रद्धालु फिसलकर गिर गए। फिर लोग एक–दूसरे के ऊपर पैर रखते हुए भागे। जो नीचे गिरा, वह उठ नहीं पाया। इसके बाद कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने घायलों को एम्बुलेंस से अस्पतालों में भर्ती करवाया। इनमें से कुछ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंन्द्र सिराऊ में भर्ती करावाया गया, वहीं कुछ को एटा और अलीगढ़ के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया।

संपादकीय

तीन आपराधिक कानूनों को नया नाम

देश में नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में, 1861 में बने तीन आपराधिक कानूनों को नया नाम मिल गया है और कई अपराधों की धाराएं बदल गई हैं। मुख्य रूप से यही काम हुआ है। बाकी कुछ नए अपराधों को इसमें शामिल किया गया है और कुछ पुराने अपराध इन कानूनों के दायरे से बाहर भी हो गए हैं। लेकिन उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। नए कानून एक जुलाई से लागू हुए हैं और उससे पहले सोशल मीडिया में इन पर मीम्स की भी बाढ़ आई थी। जैसे कई लोगों ने कहा कि अब इस देश में कोई श्री 420 नहीं होगा। अब धोखाधड़ी करने वाले को श्री 318 कहना होगा। अगर कोई राजकपूर की आईकॉनिक फिल्म श्री 420 का रिमेक बनाए तो उसे नए नाम से बनाना होगा क्योंकि सरकार ने फ्रॉड की धारा बदल दी है। इसी तरह हत्या के लिए 302 की जगह 101 धारा आ गई है और हत्या के प्रयास के लिए 307 की जगह 109 धारा लगेगी। बलात्कार के आरोप में 375 और 376 की जगह धारा 63 और 64 के तहत मुकदमा चलेगा। पुलिस वालों, वकीलों, न्यायिक अधिकारियों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को नई धाराएं याद करनी होंगी और पुरानी भी याद रखनी होंगी क्योंकि एक जुलाई 2024 से पहले के सारे मामले पुरानी धाराओं में सुने जाएंगे।

सवाल है कि इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? ज्यादातर लोग अभी तक कोई ठोस तर्क नहीं सोच पाए हैं सिवाए इसके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इतिहास में दर्ज होगा कि उन्होंने अंग्रेजों के बनाए आपराधिक कानूनों को बदला था। जो कानून 1861 से चल रहे थे और ह्यगुलामी की मानसिकताह्न का प्रतीक थे उनको 2024 में नरेंद्र मोदी ने बदल दिया। उन्होंने इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता का नाम भारतीय न्याय संहिता कर दिया। अपराध प्रक्रिया संहिता का नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया और साक्ष्य कानून का नाम भारतीय साक्ष्य संहिता कर दिया। अगर तीनों आपराधिक कानूनों में बड़े बदलाव की बात करें तो वह ये है कि भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थीं, जिन्हें कम करके 356 कर दिया गया। कई धाराएं एक दूसरे को ओवरलैप कर रही थीं तो उनको आपस में मिला दिया गया।

सीआरपीसी में पहले 484 धाराएं थीं लेकिन उसकी जगह बने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इनकी संख्या बढ़ कर 531 हो गई है। दूसरा बड़ा बदलाव यह हुआ कि कुछ अपराध की धाराएं बदल दी गईं हैं। इन धाराओं को नए सिरे से याद करना होगा। मुश्किल यह है कि देश की अदालतों में पांच करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं, जिनमें से साढ़े तीन करोड़ से ज्यादा आपराधिक मामले हैं। उन सभी साढ़े तीन करोड़ मुकदमों में पुरानी धाराओं के तहत ही सुनवाई होगी। यानी पुलिस में अभियोजन का काम देख रहे अधिकारियों, वकीलों, न्यायिक अधिकारियों आदि को 30 जून से पहले के केस के लिए पुरानी धाराएं याद रखनी हैं और एक जुलाई से जो मुकदमे दर्ज होंगे उनके लिए नई धाराएं याद रखनी होंगी। बहरहाल, तीसरा बदलाव यह है कि नए कानून में कुछ नए अपराध शामिल किए गए हैं। झांसा या लालच देकर शारीरिक संबंध बनाने पर नई धारा के तहत मुकदमा चलेगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से अदालतों ने ऐसे मामलों में राहत देनी शुरू की थी। इसी तरह विवाहित स्त्री को बरगलाने के अपराध की एक अलग धारा बनी है। माना जा रहा है कि कथित लव जिहाद रोकने की सोच के साथ ये नई धाराएं शामिल की गई हैं। नाबालिग पत्नी से संबंध बनाने को बलात्कार की श्रेणी में डाला गया है। एक दिलचस्प बात यह है कि यौन अपराधों पर इतना ध्यान देने के बाद भी सरकार ने पुरुषों के साथ बलात्कार को नए कानून से बाहर कर दिया है।

पहले समलैंगिक या अप्राकृतिक यौन व्यवहार के लिए धारा 377 के तहत मुकदमा चलता था। लेकिन अब यह धारा खत्म कर दी गई है और इसके तहत होने वाले अपराध को किसी और धारा में नहीं शामिल किया गया है। बहरहाल, मॉब लिंचिंग के लिए नया कानून बना है तो आतंकवाद को आपराधिक कानून में शामिल किया गया है। संगठित अपराध के लिए नया कानून बना है। सरकारी अधिकारियों को ड्यूटी से रोकने के लिए आत्महत्या का प्रयास करना भी अब अपराध माना जाएगा। धरने, प्रदर्शन आदि के दौरान अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं। नाम और धाराएं बदलने के क्रम में एक बड़ा बदलाव यह हुआ है कि सरकार ने राजद्रोह का नाम बदल कर देशद्रोह कर दिया है। अंग्रेजों के जमाने में राजद्रोह ही देशद्रोह था। यानी जो अंग्रेजी राज का विरोध करेगा उसे देश विरोधी माना जाएगा। कायदे से आजादी के बाद लोकतंत्र स्थापित होते ही इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए था क्योंकि लोकतंत्र में राजद्रोह जैसी कोई चीज नहीं होती है। लोकतंत्र में सत्ता का विरोध करना नागरिक का अधिकार होता है। बहरहाल, आजादी के 77 साल बाद इसका नाम बदला। हालांकि कानून जस का तस है। अपराध भी लगभग वही है, जो राजद्रोह में परिभाषित है। इसका सिर्फ नाम बदल गया है और धारा बदल गई है। पहले 124 के तहत मुकदमा चलता था और अब 152 के तहत चलेगा। जिस एक बदलाव की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है या जिसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है वह किसी आरोपी को ज्यादा लंबे समय तक पुलिस हिरासत में रखने का कानून है।

घनिष्ठ संबंधों को और आगे बढ़ाना

डॉ. लक्ष्मी शंकर यादव

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 21 एवं 22 जून की दो दिवसीय भारत यात्रा की। उनकी इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच पहले से ही बने घनिष्ठ संबंधों को और आगे बढ़ाना था।

भारत में नई सरकार के गठन के बाद यह किसी विदेशी नेता की पहली द्विपक्षीय राजकीय यात्रा थी। प्रधानमंत्री हसीना की इसी माह में यह दूसरी भारत यात्रा थी। इससे पहले वे प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारत आई थीं। इसके बाद जुलाई महीने में चीन की यात्रा पर जाएंगी। चीन की यात्रा पर जाने से पहले उनका दो बार भारत आना दर्शाता है कि चीन यात्रा से उनके भारतीय संबंधों को कोई खतरा नहीं है। इधर भारत सरकार भी बांग्लादेश से अपने मधुर संबंधों को आगे जारी रखना चाहती है।

बांग्लादेश और भारत के प्रधानमंत्रियों ने 22 जून को बैठक करके व्यापक वार्ता की। इस वार्ता में नये क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए भविष्य की योजना पर सहमति जताई और समुद्री क्षेत्र सहित अनेक मुख्य क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए तकरीबन 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित प्रमुख समझौतों में डिजिटल, हरित और रक्षा क्षेत्रों में बढ़ावा देने के समझौते शामिल हैं। इनमें बांग्लादेश के रोगियों के लिए ई–वीजा प्रमुख है। उल्लेखनीय है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेश के लोग इलाज कराने के लिए भारत आते हैं। वहां से भारत आने वाले ऐसे लोग 30 प्रतिशत के करीब हैं। ई–वीजा मिलने से ऐसे लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने नये क्षेत्रों में सहयोग के लिए भविष्योन्मुखी विजन तैयार किया है, जिसमें हरित साझेदारी, डिजिटल साझेदारी, अंतरिक्ष एवं ब्लू इकॉनमी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत–बांग्लादेश की बनी सहमति से दोनों देशों के नवयुवकों को काफी लाभ मिलेगा। दोनों देशों की ह्यमैत्री उपग्रहह्ल भारत–बांग्लादेश संबंधों को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि हम अपनी वरीयता में डिजिटल और ऊर्जा कनेक्टिविटी पर फोकस रखेंगे।

हमने पिछले 10 वर्षों में कार्य करते हुए 1965 से पहले की कनेक्टिविटी को बहाल कर दिया है। इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था गतिशील होगी। उन्होंने दोहराया, ह्यमैं बंगबंधु के स्थिर, समृद्ध और प्रगतिशील बांगलादेश के विजन को साकार रूप प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।ह्ल इन समझौतों में दूसरा समझौता बांग्लादेश के रंगपुर में भारत का नया सहायक उच्चायोग होगा। बांग्लादेश के उत्तर–पश्चिम क्षेत्र के लोगों के लिए रंगपुर में सहायक उच्चायोग खोलने का निर्णय लिया गया है। ढाका और कोलकाता के बीच नई रेल सेवा चालू की जाएगी। इसी तरह, चटगांव और कोलकाता के बीच नई बस सेवा चालू हो जाएगी। पांचवां समझौता मेदे–दरसाना और हल्दीबाड़ी–चिलाहाटी के बीच दलगांव तक मालगाड़ी सेवाओं की शुरु आत किए जाने का है।

इसके अलावा, अनुदान सहायता के तहत सिराजगंज में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का निर्माण किया जाएगा। भारतीय ग्रिड के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली के निर्यात की शुरुआत की जाएगी। 1996 की गंगा जल संधि के नवीनीकरण के लिए भी एक समिति बनाई जाएगी। रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के बीच चर्चा हुई। इसमें दोनों देशों ने लंबी अवधि के हितों को ध्यान में रख कर रक्षा सहयोग की एक नीति बनाने का निर्णय लिया है।

उल्लेखनीय है कि भारत–बांग्लादेश के बीच सैनिक और रक्षा सहयोग की गति अभी तक काफी धीमी रही है, लेकिन अब किए गए नये समझौते के बाद से भारत जो सहयोग करेगा उससे बांग्लादेश की आर्मी काफी अत्याधुनिक बनेगी। बांग्लादेश की रक्षा जरूरतों के मुताबिक रक्षा उपकरणों का उत्पादन शुरू होगा। यह कार्य इस प्रकार का होगा कि बांग्लादेश की रक्षा और यौद्धिक क्षमता काफी बढ़ सके। अभी तक भारत ने इस तरह का रक्षा समझौता किसी पड़ोसी देश के साथ नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना ने आतंकवाद, कट्टरवाद और सीमा पर शांतिपूर्ण प्रबंधन अपनी सहभागिता को मजबूत करने का भी निर्णय लिया है।

इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के मध्य हिन्द महासागर क्षेत्र के लिए समान दृष्टिकोण अपनाए जाने की बात निश्चित हुई। दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात में भारत ने बांग्लादेश की पुरानी मांग मान ली और बांग्लादेश को भूटान तथा नेपाल के साथ भारतीय रेलवे के जरिए कारोबार करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। इस स्वीकृति से बांग्लादेश को निर्यात बढ़ाने का बेहतर अवसर प्राप्त होगा। इस कदम से उत्साहित दोनों देश शीघ्र ही एक विशेष समझौता भी करने वाले हैं। अब दोनों देशों का प्रयास है कि भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के बीच एक साझा बाजार तैयार किया जा सके। यदि इस कार्य में सफलता मिल गई तो भविष्य में इस बाजार में अन्य पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, म्यांमार आदि को शामिल किया जा सकेगा। इसीलिए दोनों देश रेल, सड़क, हवाई मार्ग और समुद्री मार्ग के जरिए आवागमन और माल ढुलाई के लिए कनेक्टिवटी को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे।

प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के बीच बैठक में इस बात की भी सहमति बनी कि तीस्ता नदी जल प्रबंधन पर वार्ता के लिए भारत की एक तकनीकी टीम ढाका का दौरा करेगी। टीम तीस्ता नदी की गाद को साफ करने तथा नदी को पुराने स्वरूप में लौटाने के लिए एक रोडमैप तैयार करेगी। बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण पर बातचीत के लिए एक भारतीय दल भेजने का निर्णय इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भारत की आपत्तियों के बावजूद एक अरब अमेरिकी डॉलर की इस परियोजना पर चीन की नजर थी। यह मुद्दा भारत के लिए अत्यंत संवेदनशील है क्योंकि चीन की कंपनियों को ठेका मिलने का मतलब है कि उन्हें तीस्ता नदी से संबंधित सारा डाटा हासिल हो जाएगा। इसलिए भारत का प्रयास था कि चीन का इसमें प्रवेश न हो। इस आासन के बाद अपने देश पहुंच कर शेख हसीना ने कहा कि उनकी भारत यात्रा सार्थक रही। निश्चित है कि उपर्युक्त समझौतों के बाद भारत तथा बांग्लादेश के आपसी संबंध और अधिक मधुरता की ओर बढ़ेंगे।

आखिरकार टी–20 विश्व कप चैंपियन बना भारत

मनोज चतुर्वेदी

भारत आखिरकार, टी–20 विश्व कप में चैंपियन बन गया। उन्होंने बारबाडोस के केनसिंग्टन ओवल में खेले गए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को सात रनों से हरा कर यह सफलता हासिल की है। भारत ने टी–20 विश्व कप को दूसरी बार जीता है। इससे पहले 2007 में इसकी शुरुआत होने पर महेंद्र सिंह धोनी की अगुआई में चैंपियन बना था। धोनी की कप्तानी में ही भारत ने 2011 में वनडे विश्व कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। पर इसके बाद से सफलता रूठी रही। पिछले साल नवम्बर में भारतीय टीम वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हारी तो लगा कि टीम में चैंपियन बनने का दम नहीं है। पर सात माह में ही टीम चैंपियन का सपना पूरा करने में सफल रही। भारत जब वनडे विश्व कप में हारा तो रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल उठने लगे थे। माना जा रहा था कि किसी युवा को टीम की कमान सौंपी जा सकती है। लेकिन रोहित जब पहली बार चयन समिति से मिले तो उन्होंने कहा कि हमारी टीम के खिलाडियों को खारिज करना सही नहीं होगा क्योंकि हमने लीग चरण में चैंपियन ऑस्ट्रेलिया सहित हर टीम को हराया है। चयन समिति को इससे लगा कि रोहित टी–20 विश्व कप में कप्तानी करने को तैयार हैं। तब उन्हें ही विश्व कप में कप्तान बनाने का ऐलान हुआ। इसके बाद रोहित ने कोच राहुल द्रविड़ और सपोर्ट स्टाफ के साथ मिल कर टीम के खेलने के अंदाज को नया आयाम दिया।

इसे बाद टीम ने मुश्किल में फंसने के बाद भी आक्रामक रुख नहीं छोड़ा और यह बदलाव ही टीम को चैंपियन बनाने में सफल रहा। इस सफलता ने कोच राहुल द्रविड़ हों या कप्तान रोहित शर्मा सभी की छवि को नया रूप दे दिया है। राहुल बेजोड़ खिलाड़ी होने के बावजूद कभी विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा नहीं बन सके थे। अपनी कप्तानी में बारबाडोस में ही वनडे विश्व कप में खराब प्रदर्शन से दो–चार हो चुके थे। लेकिन अब इसी मैदान से विश्व कप जिताने वाले कोच के तौर पर अपनी इस पारी को विराम दे रहे हैं। जहां तक बात रोहित की है तो वह अपनी कप्तानी में टीम को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे विश्व कप के फाइनल में ले जा चुके थे पर चैंपियन कप्तान का टेग उनके ऊपर नहीं लग सका था। वह भारत को वनडे और टी–20 रैंकिंग में नंबर एक पर पहुंचाने में सफल रहे पर फिर भी विश्व कप जीतने वाले कप्तानों कपिल देव की जमात में शामिल नहीं हो सके थे पर अब टी–20 विश्व कप जीत कर वह इस जमात में शामिल हो गए हैं। रोहित और द्रविड़ की कप्तान–कोच की जोड़ी की तरह ही विराट और रवि शास्त्री की जोड़ी ने भी टीम को ढेरों सफलताएं दिलाई पर टीम को विश्व कप नहीं जिता सकी। पर विराट इससे पहले वनडे विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीमों में शामिल रहे थे और उनकी कप्तानी में भारत अंडर–19 विश्व कप भी जीत चुका था। अब टी–20 विश्व कप भी उनकी झोली में आ गया है। वह चारों ट्रॉफियां जीतने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं।

भारत ने जिस तरह से फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को फतह किया, उसे सालों–साल याद रखा जाएगा। भारत ने जब पहले बल्लेबाजी करके सात विकेट पर 176 रन बनाए तो यह लगा कि वह जरूरत से 10–15 रन पीछे रह गया।

न्याय की अवधारणा पर आधारित हैं नये आपराधिक कानून

–डॉ. मोहन यादव

भारत में आपराधिक कानूनों में परिवर्तन और सुधार एक महत्वपूर्ण विषय है, जो समाज की बदलती आवश्यकताओं और न्याय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समय–समय पर किया जाता है। हाल ही में, भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे आपराधिक कानूनों को संसद में पारित किया गया। अब एक जुलाई 2024 से पूरे देश में यह लागू हो रहा है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने संसद में कानून को पेश करते हुए कहा कि खत्म होने वाले ये तीनों कानून अंग्रेज़ी शासन को मज़बूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे । इनका उद्देश्य दंड देने का था, न की न्याय देने का। तीन नए कानून की आत्मा भारतीय नागरिकों को संविधान में दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना, इनका उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना होगा। भारतीय आत्मा के साथ बनाए गए इन तीन कानूनों से हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा।पुराने कानूनों में गुलामी की बू आती थी। ये तीनों पुराने कानून गुलामी की निशानियों से भरे हुए थे क्योंकि इन्हें ब्रिटेन की संसद ने पारित किया था और हमने सिर्फ इन्हें अपनाया था। इन कानूनों में पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, प्रोविंशियल एक्ट, नोटिफिकेशन बाई द क्राउन रिप्रेज़ेन्टेटिव, लंदन गैज़ेट, ज्यूरी और बैरिस्टर, लाहौर गवर्नमेंट, कॉमनवेल्थ के प्रस्ताव, यूनाइ-टेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड पार्लियामेंट का ज़िक्र है। इन कानूनों में हर मैजेस्टी और बाइ द प्रिवी काउंसिल के रेफरेंस दिए गए हैं, कॉपीज़ एंड एक्सट्रैक्ट्स कंटेंट इन द लंदन गैज़ेट के आधार पर इन कानूनों को बनाया गया, पज़ेशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंग्लैंड और हर मैजेस्टी डॉमिनियन्स का भी ज़िक्र इन कानूनों में कई स्थानों पर है। अच्छी बात यह कि गुलामी की निशानियों को पूरी तरह मिटा दिया गया है। जिसके तहत 475 जगह गुलामी की निशानियों को समाप्त कर दिया गया है। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत समय लगता है, कई बार न्याय इतनी देर से मिलता है कि न्याय का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, लोगों की श्रद्धा उठ जाती है और अदालत में जाने से डरते हैं।इन कानूनों को बनाने के पीछे बहुत लंबी प्रक्रिया रही है। इन कानूनों को आज के समय के अनुरूप बनाने में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अगस्त, 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों, देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और देश के सभी कानून विश्वविद्यालयों को पत्र लिखे थे। वर्ष 2020 में सभी, महामहिम राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और सांसदों एवं संघ–शासित प्रदेशों के महामहिम प्रशासकों को पत्र लिखे गए। इसके बाद व्यापक परामर्श के बाद ये प्रक्रिया कानून बनने जा रही है। इसके लिए 18 राज्यों, 6 संघशासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक अकादमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद, लगभग 270 विधायकों और जनता ने इन नए कानूनों पर अपने सुझाव दिए हैं। यह प्रक्रिया सरल नहीं थी, काफी मेहनत की गई बीते 4 सालों में। खूब विचार विमर्श किया गया है। इस संदर्भ में हुई 158 बैठकों में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह उपस्थित रहे हैं।

इन कानूनों में क्या बदलाव हुआ है, इस पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने बताया कि आज तक आतंकवाद से परिचित सभी थे लेकिन आतंकवाद की परिभाषा, व्याख्या नहीं थी। अब ऐसा नहीं रहेगा। अब अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने जैसे अपराधों की पहली बार इस कानून में व्याख्या की गई है। इससे जुड़ी संपत्तियों को ज़ब्त करने का अधिकार भी दिया गया है। जांचकर्ता पुलिस अधिकारी के संज्ञान पर कोर्ट इसका आदेश देगा। गौरतलब है कि अनुपस्थिति में ट्रायल के बारे में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है। सेशंस कोर्ट के जज द्वारा प्रक्रिया के बाद भगोड़ा घोषित किए गए व्यक्ति की अनुपस्थिति में ट्रायल होगा और उसे सज़ा भी सुनाई जाएगी, चाहे वो दुनिया में कहीं भी छिपा हो। उसे सज़ा के खिलाफ अपील करने के लिए भारतीय कानून और अदालत की शरण में आना होगा। अभी तक देखा गया है कि देश भर के पुलिस स्टेशनों में बड़ी संख्या में केस संपत्तियां पड़ी रहती हैं। अब इस ओर भी तेजी लाई जाएगी। यानी अब इनकी वीडियोग्राफी करके सत्यापित प्रति कोर्ट में जमा करके इनका निपटारा किया जा सकेगा।इन कानूनों में अत्याधुनिकतम तकनीकों को समाहित किया गया है। दस्तावेज़ों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ई–मेल, सर्वर लॉग्स, कम्प्यूटर, स्मार्ट फोन, लैपटॉप्स, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस को कानूनी वैधता दी गई है, जिनसे अदालतों में लगने वाले कागज़ों के अंबार से मुक्ति मिलेगी। इस कानून को डिजिटलाइज किया गया है, यानी एफआईआर से केस डायरी, केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज़ करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। अभी सिर्फ आरोपी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है, लेकिन अब पूरा ट्रायल, क्रॉस क्वेश्चनिंग सहित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संभव होगी। शिकायतकर्ता और गवाहों का परीक्षण, जांच–पड़ताल और मुक़दमे में साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग और उच्च न्यायालय के मुक़दमे और पूरी अपीलीय कार्यवाही भी अब डिजिटली संभव होगी। सर्च और ज़ब्ती के समय वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया है, जो केस का हिस्सा होगी और इससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होगी।

आजादी के 75 सालों के बाद भी दोष सिद्धि का प्रमाण बहुत कम है। यही कारण है कि मोदी सरकार ने फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा देने का काम किया है। तीन साल के बाद हर साल 33 हज़ार फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट्स देश को मिलेंगे। साथ ही श्री अमित शाह ने लक्ष्य रखा है कि दोष सिद्धि के प्रमाण को 90 प्रतिशत से ऊपर लेकर जाना है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि 7 वर्ष या इससे अधिक सज़ा वाले अपराधों के क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को अनिवार्य किया जा रहा है। इसके माध्यम से पुलिस के पास एक वैज्ञानिक साक्ष्य होगा जिसके बाद कोर्ट में दोषियों के बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।

गुरमीत चौधरी की वेब सीरीज कमांडर करण सक्सेना का ट्रेलर जारी, एक्शन अवतार में नजर आए अभिनेता

टीवी इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने के बाद एक्टर गुरमीत चौधरी अब ओटीटी पर एक्शन अवतार में नजर आएंगे। उनकी अपकमिंग स्ट्रीमिंग सीरीज कमांडर करण सक्सेना का ट्रेलर रिलीज हुआ।

ट्रेलर में उनका किरदार रॉ एजेंट करण सक्सेना का है, जो देशभक्त है और भारत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वहीं, इकबाल खान विलेन के रोल में हैं। उन्होंने आईएसआई चीफ नासिर का किरदार निभाया है।

सीरीज के बारे में गुरमीत चौधरी ने कहा, कमांडर करण सक्सेना मेरे लिए बेहद खास है। मैं उन सभी अधिकारियों की दिल से तारीफ करता हूं, जो देश की जी जान से सेवा करते हैं। इन हीरो से प्रेरित एक किरदार को निभाना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। सीरीज में मेरा किरदार करण देश के प्रति समर्पित है। इस किरदार को मैं असल जिंदगी में भी अपनाना चाहता हूं। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो मैं हमेशा से बनना चाहता था।

सीरीज का निर्देशन जतिन वागले ने किया है और इसका निर्माण कीलाइट प्रोडक्शंस ने किया है। एक्टर इकबाल खान ने कहा, यह मेरे द्वारा निभाए गए सबसे खतरनाक और आकर्षक किरदारों में से एक है। नासिर आक्रामक है। नासिर का किरदार निभाने से मुझे कुछ अलग किरदार को आजमाने का मौका मिला। यह एक चुनौतीपूर्ण अनुभव था। मुझे उम्मीद है कि दर्शक हमारी कड़ी मेहनत को देख पाएंगे और सीरीज को एन्जॉय करेंगे। यह कहानी निश्चित रूप से दर्शकों को प्रेरित करेगी। हाल ही में कमांडर करण सक्सेना का टीजर जारी किया गया था। इसकी जिसकी शुरुआत में इकबाल खान दिखाई देते हैं और बैकग्राउंड से आवाज आती है कि कफन तैयार कर लो, तुम्हारा मुल्क जलाकर तबाह करने वाले हैं। इसके बाद गुरमीत का जबरदस्त डायलॉग आता है, जिसमें एक्टर कहते हैं, इतने साल में एक क्रिकेट मैच तो हरा नहीं पाए, मेरे देश को हराने चले हो। टीजर को दर्शकों ने काफी पसंद किया। यह सीरीज 8 जुलाई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है।

जोकोविच बिना किसी परेशानी के दूसरे दौर में, महिला गत चैंपियन बाहर

लंदन, 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ग्रास कोर्ट पर अपना मास्टर क्लास दिखाते हुए चेक गणराज्य के विट कोपरीवा को लगातार सेटों में 6–3, 6–2, 6–2 से हराकर वर्ष के तीसरे ग्रैंड स्लैम विम्बलडन के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया जबकि महिला वर्ग में गत चैंपियन मार्केटा वोन्द्रूसोवा पहले दौर में हारकर बाहर हो गयीं।

घुटने की चोट के कारण फ्रेंच ओपन से हटने वाले जोकोविच ने अपनी शानदार वापसी में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं दिखाई और पूरे मुकाबले के दौरान वो सहज दिखे। जोकोविच ने मैच के दौरान सिर्फ 16 बेजां भूलें कीं और अपनी पहली सर्विस पर 90 फीसदी अंक बटोरे। इस बीच चौथी सीड जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव शानदार शुरुआत करते हुए रॉबर्टो कार्बालेस बायेना को 6–2, 6–4, 6–2 से हराकर आठ बार टूर्नामेंट में अपनी उपस्थिति में से सातवीं बार दूसरे दौर में पहुंच गए। ज्वेरेव ने मैच में 18 एस सहित 46 विनर्स लगाए। उधर विश्व नंबर छह आंद्रेई रूब्लेव पहले दौर में हारकर टूर्नामेंट में अब तक बाहर होने वाले सर्वोच्च रैंक के खिलाड़ी बन गए।

आईपीएल 2025 के ऑक्शन को लेकर जल्द आ सकता है बड़ा अपडेट

नईदिल्ली, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के मेगा ऑक्शन को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, ज्यादातर फ्रेंचाइजी ने रिटेंशन की संख्या बढ़ाने की मांग की है. आईपीएल टीमों ने रिटेंशन खिलाड़ियों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 से 7 के बीच करने की मांग की है. रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि एक टीम ने ज्यादा से ज्यादा 8 खिलाड़ियों को रिटेन करने की मांग की है, लेकिन सभी फ्रैंचाइजी इस पर एकमत नहीं हैं, क्योंकि उनमें से कुछ ने किसी को रिटेन न करने की मांग की है. साथ ही, कोई रिटेंशन न रखने और केवल राइट टू मैच कार्ड रखने का अनुरोध किया गया था.

वहीं बीसीसीआई के कार्यवाहक सीईओ और आईपीएल प्रभारी हेमंग अमीन ने हाल ही में सभी फ्रेंचाइजियों के सीईओ से अगले तीन सालों के लिए सैलरी सीमा और नीति पर उनके विचार जानने की कोशिश की. उनसे आरटीएम कार्ड के बारे में भी पूछा गया. बीसीसीआई ने कहा है कि वह टीमों के मालिकों के बीच होने वाली मीटिंग में फैसले का एलान करेंगे. इसका एलान इसी महीने किया जा सकता है. वहीं फ्रेंचाइजी के सीईओ से टीम के पर्स के बारे में भी पूछा गया. मौजूदा समय में, टीम का पर्स 100 करोड़ रुपए है. अब राय यह दी गई है कि वेतन सीमा 110–120 करोड़ रुपए के बीच रखी जाए, लेकिन इसमें 20 करोड़ की बढ़ोतरी हो सकती है.रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस दौरान इम्पैक्ट प्लेयर नियम पर भी चर्चा की गई. मीडिया राइट्स वाले इस नियम से खुश हैं, लेकिन कुछ टीमों के कोचिंग स्टाफ इस नियम से बहुत ज्यादा खुश नहीं है. बता दें कि इम्पैक्ट प्लेयर का नियम साल 32023 में लागू किया गया था, लेकिन रोहित शर्मा समेत कई दिग्गज खिलाड़ियों ने इसकी आलोचना की और कहा कि यह नियम ऑलराउंडर खिलाड़ियों के लिए सही नहीं है.

रितेश देशमुख की पहली वेब सीरीज पिल का ट्रेलर जारी, खोलेंगे फार्मा कंपनी के धंधे की पोल

रितेश देशमुख बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता हैं, जो किसी भी किरदार में जान फूंकना बखूबी जानते हैं। कॉमेडी हो या फिर नेगेटिव रोल उनकी हर भूमिका लोगों को काफी पसंद आती है। बिग स्क्रीन के बाद अब वह धीरे–धीरे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। उनकी साल 2022 में प्लान ए–प्लान बी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बाद अब वह वेब सीरीज में भी अपना डेब्यू कर रहे हैं। रितेश एक बार फिर से पिल के साथ फिर दर्शकों के बीच ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लौट रहे हैं, जिसका धमाकेदार ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है।

रितेश देशमुख के आगामी प्रोजेक्ट की कहानी उनकी पिछली फिल्मों से बिल्कुल हटकर है। पिल का 1 मिनट 50 सेकंड का ये ट्रेलर वाकई शानदार है। रितेश देशमुख ने इस सीरीज में डॉ प्रकाश चौहान का किरदार अदा कर रहे हैं, जो कंपनी का डिप्टी मेडिसिन कंट्रोलर है। इस ट्रेलर की शुरुआत में दिखाया गया है कि कैसे दवाई के गोरखधंधे का जाल बहुत–बहुत दूर–दूर तक फैला हुआ है। कुछ ऐसी कंपनी हैं, जो लंका की तरह हैं और उस पर अंकुश लगाने के लिए एक रामनगरी बनी हुई जो है मेडिसिन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस छोटी सी झलक में एक सच्चाई उगाजर की गयी है कि कैसे एक फार्मा कंपनी की बनी दवाइयां खाकर कुछ लोगों की मौत हो रही है और कुछ लोग बीमार पड़ रहे हैं। जिसके बाद उस फार्मा कंपनी की जांच–पड़ताल की जाती है और वहीं से पूरा ड्रामा अनफोल्ड होता है। कंपनी के मालिक रितेश देशमुख को धमकी देते हुए भी ट्रेलर में दिखाई दे रहे हैं। अब कंपनी की छान–बीन करते हुए उनकी जिंदगी में क्या भूचाल आएगा, ये तो सीरीज की रिलीज के बाद ही पता लगेगा।

बॉलीवुड में कदम रखने को तैयार श्रीलीला

पिछले दिनों अभिनेता वरुण धवन पिता बने हैं। उनकी पत्नी नताशा दलाल ने 3 जून को हिंदुजा अस्पताल में एक प्यारी बेटी को जन्म दिया था।निजी जिंदगी के अलावा वरुण अपनी फिल्मों को लेकर भी चर्चा में हैं।फिलहाल वरुण के हाथ में कई फिल्में हैं, जिनमें एक नाम उनके पिता डेविड धवन के निर्देशन में बन रही फिल्म भी शामिल है।खबर है कि वरुण की इस फिल्म के जरिए श्रीलीला बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, डेविड की अगली निर्देशित फिल्म से वरुण के साथ साउथ की अभिनेत्री श्रीलीला बॉलीवुड में कदम रखने के लिए तैयार हैं।बताया जा रहा है कि श्रीलीला फिल्म में वरुण की गर्लफ्रेंड की भूमिका निभाएंगी।

यूरो 2024: तुर्की ने ऑट्रेलिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

लीपजिग, मेरिह डेमिरल के दो गोल की बदौलत तुर्की ने मंगलवार देर रात लीपजिग के रेड बुल एरिना में यूरो 2024 के 16वें राउंड के मैच में ऑस्ट्रिया को 2–1 से हरा दिया। तुर्की ने मुकाबले की शानदार शुरुआत की और यूरो टूर्नामेंट के नॉकआउट चरणों में सबसे तेज गोल करने का रिकॉर्ड भी बनाया। ऑस्ट्रिया कॉर्नर के बाद गेंद को क्लियर नहीं कर सका, जिससे डेमिरल ने मैच के 57 सेकंड बाद ही पहला गोल कर दिया। ऑस्ट्रिया ने भी पलटवार किया, लेकिन क्रिस्टोफ़ बॉमगार्टनर ने बराबरी हासिल करने के दो मौके गंवा दिए। ऑस्ट्रियाई टीम तुर्की के खिलाफ अधिक मौके बनाने के लिए संघर्ष करती रही और ब्रेक तक गोलरहित रही। इस बीच, विन्सेन्ज़ो मोंटेला की टीम खतरनाक बनी रही, डेमिरल ने एक और गोल किया। जिससे तुर्की 2–0 से आगे हो गई। जवाब में, ऑस्ट्रिया ने गति पकड़ी और तुर्की के डिफेंस को कड़ी टक्कर दी। हालांकि, मार्को अरनॉटोविक गोलकीपर मर्ट गुनोक को नहीं हरा पाए। ऑस्ट्रिया ने बराबरी की तलाश में हर खिलाड़ी को आगे बढ़ाया, जबकि तुर्की ने अपने सभी खिलाड़ियों को गेंद के पीछे रखा, ताकि जवाबी हमले के अवसरों की प्रतीक्षा की जा सके। बारिस यिलमाज के पास इन जवाबी हमलों को खत्म करने का सुनहरा मौका था, लेकिन बॉक्स के अंदर से गोलकीपर पैट्रिक पेंट्ज़ को चकमा देने के लिए वे लक्ष्य से चूक गए। इस परिणाम के साथ, तुर्की 2008 के बाद पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया, जहां शनिवार को बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में उसका सामना नीदरलैंड से होगा। ऑस्ट्रिया के कोच रैंगनिक ने कहा, हमें भाग्य का साथ नहीं मिला और मेरा मानना है कि अगर मैच अतिरिक्त समय तक चला होता, तो हम जीत जाते।

एक नजर

कार्यक्रम सात जुलाई को

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : 17-गौरव सेनानी समिति की ओर से बटालिक बैटल ऑनर डे (सिल्वर जुबली) सात जुलाई को धूमधाम से मनाया जाएगा। जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष जगदीश पोखरियाल व सचिव भारत भूषण बलूनी ने बताया कि कार्यक्रम निंबूचौड़ स्थित एक फार्म हाउस में होगा। कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी।

बारिश से पांच ग्रामीण सड़कें बंद, लोग परेशान

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : पौड़ी मुख्यालय के साथ ही जिले के विभिन्न हिस्सों में बुधवार को दिन भर रुक-रुक कर बारिश होती रही। बारिश के कारण जिले में पांच ग्रामीण सड़कें अवरुद्ध हुई। जिस कारण यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सड़कें खोलने के लिए लोनिवि ने जेसीबी लगाई है।

जिले की तहसील लैंसडौन क्षेत्र में सबसे अधिक 38 एमएम बारिश रिकार्ड की गई। जबकि कोटद्वार तहसील क्षेत्र में भी 28 एमएम बारिश हुई। चाकीसैंण तहसील क्षेत्र में 15 एमएम तो यमकेश्वर में 10 एमएम बारिश हुई। बारिश के कारण सड़कों पर जगह-जगह मलबा भी आ गया। जो सड़कें बुधवार को आवाजाही के लिए बंद रही उनमें गैंडखाल-आमसैंण, छिनखाल-कमेडा, नैनीडांडा-शंकरपुर, शंकरपुर-बैडहाट और भदोली सड़क शामिल है।

आउटसोर्स कर्मचारियों ने शुरू किया कार्य बहिष्कार

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : जल संस्थान के आउटसोर्स कर्मियों ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। पौड़ी के जल संस्थान विभाग के तहत आने वाले आउटसोर्स कर्मचारी मानदेय का भुगतान समय पर न होने से आक्रोशित है। कर्मचारियों का कहना है कि मानदेय को लेकर कई बार विभाग को लिखित एवं मौखिक रूप से अवगत कराया गया, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बुधवार को कार्य बहिष्कार करते हुए कर्मचारियों ने कहा कि कई बार मानदेय बढ़ाने व समय से भुगतान को लेकर विभाग को अवगत कराया गया, लेकिन उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। कहा कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं, जलकल कर्मियों की हड़ताल का असर शहर की पेयजल आपूर्ति पर ना पड़े इसको लेकर जल संस्थान के अधिशासी अभियंता एसके रॉय ने बताया कि स्थाई जलकल कार्मिकों के जरिए व्यवस्था बनाई जा रही है। बताया कि यह स्थिति क्यों आई है इसको लेकर संबंधित ठेकेदार से भी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और कर्मचारियों की समस्या हल की जाएगी। कार्य बहिष्कार करने वालों में शिवचरण, राजा, पदम, राकेश, महाराज, गोपी कृष्ण, इंद्रमोहन, असलम, विक्की आदि शामिल थे।

बारिश से मौसम हुआ सुहावना

श्रीनगर गढ़वाल : श्रीनगर और आस पास के क्षेत्र में बुधवार सुबह से ही हल्की बारिश ने दस्तक दी। हल्की बारिश के चलते जहां लोगों को गर्मी से निजात मिली वहीं मौसम भी सुहावना हुआ। श्रीनगर में बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई। दिनभर आसमान में काले बादल छाए रहें हल्की बारिश ने मौसम को कुछ हद तक ठंडा किया। मानसून की पहली बारिश होने पर लोगों के चेहरे खिले नजर आए। और लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली।

जिले में जल्द होगें प्राइमरी शिक्षकों के तबादलें

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : जनपद में प्राइमरी शिक्षकों के जल्द तबादलें होगें। बेसिक शिक्षकों के तबादलों की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है। जिले में लगभग साढ़े पांच सौ शिक्षक स्थानान्तरण के लिए पात्र है।

इससे पूर्व एडीएम की अध्यक्षता में तबादला समिति की बैठक में शिक्षकों के तबादलों को लेकर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। ऑन लाइन पोर्टल पर शिक्षकों की सूची को अपलोड किए जाने की तैयारियां इन दिनों चल रही है। पोर्टल पर इससे पहले जिले में रिक्त पदों से लेकर पात्रता की सूची अपलोड कर दी गई थी। अब सुगम से दुर्गम, दुर्गम से सुगम, पति -पत्नी आदि विभिन्न श्रेणियों के तबादलों की जद में आने वाले शिक्षकों की सूची भी ऑन लाइन कर दी जाएगी। पौड़ी के डीईओ बेसिक नागेंद्र बर्तवाल ने बताया कि समिति की बैठक के बाद तबादलों को लेकर सूची बनाई जा रही है। जिले में करीब साढ़े पांच सौ शिक्षक तबादलों के लिए पात्र हैं। अब शिक्षकों के नामों की सूची भी ऑनलाइन करने को लेकर काम हो रहा है। दो-तीन दिन के अंदर यह सूची ऑनलाइन कर दी जाएगी। इसके बाद तबादलों को लेकर एक सप्ताह के भीतर आपत्तियां भी मांगी जाएगी।

फिर डराने लगा पनियाली गदेरा, महज नोटिस तक सिमटा सिस्टम

प्रतिवर्ष बरसात में तबाही मचाता है नगर के बीच से गुजरने वाला पनियाल गदेरा ◆ गदेरे को अतिक्रमण मुक्त करने के नाम पर केवल चिह्निकरण व नोटिस तक सिमटा सिस्टम

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : बरसात की धमक के साथ ही पनियाली गदेरा एक बार फिर क्षेत्रवासियों को डराने लगा है। पहाड़ों में हो रही तेज बारिश के दौरान नगर के बीच से गुजरने वाला पनियाली गदेरा विकराल होकर बह रहा है। अतिक्रमण की भेंट चढ़ा यह गदेरा कब जान-माल पर भारी पड़ जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। जबकि पूर्व में भी गदेरा क्षेत्र में काफी तबाही मचा चुका है।

बुधवार को बारिश के दौरान उफान पर बहता पनियाली गदेरा

घाड़ क्षेत्र के जंगल से निकलने वाला पनियाली गदेरा नगर के बीच से होकर गुजरता है। ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही वर्षा कोटद्वार के लिए दुखःदायी साबित होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में मूसलधार बारिश होने पर कोटद्वार क्षेत्र में गदेरा उफान पर आ जाता है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के समीप से गदेरा नगर निगम क्षेत्र में प्रवेश करता है। इसके बाद शिवपुर, आमपड़ाव, मानपुर, सिताबपुर, काशीरामपुर, कौड़िया क्षेत्रों से होता हुआ सुखरो नदी तक पहुंचता है। जंगल से जैसे ही यह गदेरा शहर में प्रवेश करता है, गदेरे का आकार सिकुड़ने लगता है। इसके बाद जैसे-जैसे गदेरा मानपुर, सिताबपुर, जानकीनगर, सूर्यानगर, शिवालिक नगर, देवी नगर, कौड़िया बस्ती से गुजरता है, गदेरा गंदे नाले के रूप में नजर आने लगता है। पूर्व में उफान पर बने गदेरे से कई बार जानमाल का नुकसान हो चुका है। गत वर्षाकाल के दौरान भी कौड़िया क्षेत्र में गदेरे ने खूब तांडव मचाया था। कई लोगों के घरों में मलबा भर गया था।

चिह्निकरण तक सिमटा अभियान

करीब पांच वर्ष पूर्व सिंचाई विभाग ने पनियाली गदेरे में आमपड़ाव से कौड़िया के मध्य 130 अतिक्रमण चिह्नित किए। लेकिन, आज तक इस अतिक्रमण को हटाने की जहमत नहीं उठाई। बीते वर्षाकाल में पुनः सिंचाई विभाग ने अतिक्रमण चिह्निकरण की कार्रवाई की और 156 अतिक्रमण चिह्नित किए। लेकिन, पूर्व की भांति इस मर्तबा भी विभाग अतिक्रमणकारियों को नोटिस देने तक ही सिमट कर रह गया। स्थानीय प्रशासन भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही को लेकर चुप्पी साधे नजर आता है।

पनियाली गदेरे में हुए हादसे

1. वर्ष 1988 में पनियाली गदेरे में आई बाढ़ से दो लोगों की मौत। गदेरे से सटे क्षेत्रों में भारी नुकसान
2. वर्ष 1993-94 में गदेरे में आई बाढ़ से निचले क्षेत्रों में कई घरों में पानी भर गया। कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन लोगों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ।
3. 16 सितंबर 2012 को सूर्या नगर में बनी पुलिया के कारण गदेरे का पानी सूर्या नगर व कौड़िया क्षेत्र में भरा, भारी नुकसान।
4. अगस्त 2017 को पनियाली गदेरे से आई बाढ़ के कारण सात लोगों की मौत, पूरे क्षेत्र में जलभराव, हजारों घरों में भरा मलबा
5. अगस्त 2018 में पनियाली गदेरे के उफान पर आने के बाद कई घरों में मलबा घुसा, एक महिला की मौत
6. जुलाई 2019 में घर में गदेरे का पानी भर जाने के बाद सामान बाहर निकाल रहे तीन युवकों की करंट लगने से मौत
7. सात अगस्त 2023 में पनियाली गदेरे ने कौड़िया क्षेत्र में जमकर उत्पात है। गदेरे के तेज बहाव में गढ़वाल राइफल्स रेजीमेंटल सेंटर के विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह कैंप को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली पुलिया बह गई। साथ ही कुछ आवासों को भी नुकसान पहुंचा।

कोटद्वार में खोला जाएं एलोपैथिक वैलनेस सेंटर

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : शहरवासियों की सुविधा को देखते हुए वरिष्ठ नागरिक संगठन ने कोटद्वार में एलोपैथिक वैलनेस सेंटर खुलवाने की मांग की है। कहा कि सुविधा के अभाव में शहरवासियों को देहरादून सहित अन्य शहरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। जिससे उनका पैसा व समय दोनों बर्बाद होता है।

वरिष्ठ नागरिक संगठन के अध्यक्ष पीएल खंतवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस का लाभ क्षेत्र के अर्द्ध सैनिकों, केंद्र सरकार के सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है। कहा कि यह सुविधा सिर्फ देहरादून में ही उपलब्ध है। लोगों को डाक्टर से परामर्श लेने के लिए देहरादून के चक्कर काटने पड़ते हैं। कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से देश में नए स्वास्थ्य केंद्र वैलनेस सेंटर खोलने के लिए 21 स्थानों पर संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। लेकिन, इसमें हल्द्वानी व नैनीताल के ही नाम शामिल है, जबकि कोटद्वार भी उपयुक्त स्थान है। कोटद्वार में वैलनेस सेंटर खुल जाने से सभी लोगों को सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से कोटद्वार में स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की मांग की है।

नाले में अतिक्रमण से नहीं हो रही पानी की निकासी

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : स्व. सरोजनी देवी लोक विकास समिति ने सुमन देव मार्ग पर अतिक्रमण के कारण पानी की निकासी नहीं होने पर रोष व्यक्त किया है। कहा कि कुछ लोगों ने नाले पर अतिक्रमण कर दिया है। जिसके कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही है।

इस संबंध में समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह नेगी ने पुलिस को शिकायत की है। कहा कि वर्तमान में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में सुमन देव मार्ग पर निकासी नहीं होने के कारण बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। आसपास के कई लोगों ने नाली के ऊपर पक्का निर्माण करवाकर उसे अपना पार्किंग स्थल बना दिया है। कहा कि व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए जल्द ही इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

सिस्टम की कार्यप्रणाली पर जताया रोष

● राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रभावितों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : सनेह क्षेत्र में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रभावितों ने प्रशासन पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाया है। कहा कि पट्टधारकों को बेघर करने की योजना बनाई जा रही है। पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना परिवारों को बेदखल करना गलत है।

समस्या के संबंध में प्रभावितों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। प्रभावित चंदर सिंह, महिपाल सिंह, लक्ष्मण सिंह, अब्दुल रहमान का कहना है कि प्रस्तावित राजमार्ग से अनुसूचित जाति, जनजाति व गरीब लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। शासन-प्रशासन की तरफ से अभी तक उनके पुर्नवास की व्यवस्था नहीं की है और न ही मुआवजे का प्राविधान किया है, जिस कारण उनमें भविष्य को लेकर चिंता बनी हुई है। कहा कि शासन-प्रशासन का विशेष वर्ग के लोगों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिलाधिकारी से मामले में हस्तक्षेप कर प्रभावितों के पुर्नवास की समुचित व्यवस्था करने व उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की गई। मांग न माने जाने पर परिवार सहित आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। ज्ञापन सौंपने वालों में पूरण सिंह, राजकुमार, मनबहादुर, अनिल, दीपा देवी, सरोजनी देवी, आशा देवी, कौशल्या देवी मौजूद रहे।

भाजपा व भाजयुमो ने फूंका राहुल गांधी का पुतला

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : हिंदुओं को हिंसक बताने वाले बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी व भाजयुमो ने कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी का पुतला दहन किया। कहा कि इस तरह की बयानबाजी कर राहुल गांधी हिंदुओं की भावनाओं से खेल रहे हैं। अपने इस बयान के लिए राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी नगर व भाजयुमो के कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए झंडाचौक में पहुंचे। यहां उन्होंने राहुल गांधी का पुतला दहन करते हुए कांग्रेस पर हिंदुओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया। कहा कि पूर्व में सत्ता में रहने के दौरान कांग्रेस ने हिंदुओं पर अत्याचार किया और आज खुलेआम लोकसभा सत्र में हिंदुओं को हिंसक कहा जा रहा है। इस तरह की गलती करने पर राहुल गांधी को सदन से निष्कासित किया जाना चाहिए। देश में विकास के नाम पर राजनीति होनी चाहिए।

कोटद्वार के झड़ाचौक में राहुल गांधी का पुतला दहन करते भाजपाई

इस मौके पर संग्राम सिंह भंडारी, गजेंद्र रावत, शांतनु रावत, संजय सिंह रावत, आशीष सतीजा, रजनीश चौधरी, राजेंद्र जजेड़ी, बबीता सिंह, नवीन भट्ट, संजीव थपलियाल, शुभम रावत, हेमंत गौड़, विजय रावत, मुकुल नेगी, नमन, हार्दिक, यश वेदी, गौतम भाटिया आदि मौजूद रहे।

सरकारी जमीन को कब्जाने का आरोप लगाया

देहरादून। तहसील विकासनगर स्थित ठाकुरपुर गांव के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को कलक्ट्रेट पहुंचकर कर डीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने कुछ लोगों पर करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन को कब्जाने का आरोप लगाया है।

एसडीएम सदर के माध्यम से डीएम को ज्ञापन भेजकर कब्जा करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

वैकल्पिक मार्ग की निगरानी करें अधिकारी

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक ऋतु खण्डूडी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा की स्थानीय समस्याओं पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को बुधवार को पत्र लिखकर जवाब मांगा है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखकर मालन नदी पर पॉकलैंड और जेसीबी के माध्यम से दोनों कॉजवे पर पानी डायवर्ट करने के लिए निर्देशित करने के साथ ही लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए भी आदेशित किया। कहा कि दो तीन दिन की बारिश में ही मालन नदी के उफान पर आ जाने से ह्यूमपाइप कॉजवे वैकल्पिक मार्ग के ऊपर से पानी बहने लगा जिस कारण यातायात बाधित हो रहा है। इसे सही किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने देवी रोड व अन्य जगहों पर डाले मलबे को नहीं उठाने पर नगर आयुक्त को जवाब देने को कहा। नगर निगम की इस लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने नगर आयुक्त को तुरंत सफाई करवाने के साथ ही कूड़ा उठाने के लिए निर्देशित किया।

लखनऊ से कोटद्वार-रामनगर बस संचालन की मांग

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : लखनऊ से उत्तराखण्ड कोटद्वार एवं रामनगर के लिए बस संचालन की मांग कोलेकर अखिल भारतीय उत्तराखण्ड महासभा का शिष्ट मंडल दया शंकर सिंह राज्य परिवहन (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री से मिला।

बुधवार को महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भावन सिंह रावत के नेतृत्व में एक शिष्ट मंडल ने उत्तर प्रदेश परिवहन राज्यमंत्री दया शंकर के लखनऊ स्थित आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उत्तराखण्ड प्रवासियों की समस्या के बारे में बताया कि कोटद्वार एवं रामनगर से आने जाने हेतु लखनऊ से कोई भी सीधी बस सर्विस नहीं है। जिस कारण प्रवासियों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जनहित में लखनऊ से उत्तराखण्ड कोटद्वार एवं रामनगर के लिए बस का संचालन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में परिवहन मंत्री ने तुरंत फोन कर सम्बंधित अधिकारी को बस संचालन के लिए आदेश दिया। इस मौके पर राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अशोक असवाल, लखनऊ शाखा अध्यक्ष अवधेश कोठारी, महामंत्री जगदीश बुटोला, सांस्कृतिक सचिव प्रेम सिंह बिष्ट, उपाध्यक्ष बहादुर सिंह बिष्ट, पूरन सिंह बिष्ट आदि मौजूद थे।

कर्मचारियो ने किया बहिष्कार, पदों को बहाल करने की मांग

श्रीनगर गढ़वाल : उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन के आह्वान पर आयकर विभाग के कर्मचारियों ने बुधवार को श्रीनगर में आयकर विभाग के कार्यालय के सामने दो घंटे तक कार्य बहिष्कार किया। महेश जुयाल, मनोज कुमार, सत्य शाह ने राज्य कर अधिकारी के पदों पर कटौती का विरोध किया।

कर्मचारियों ने कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। कहा कि राज्य कर विभाग में राज्य कर अधिकारियों के पदों की संख्या में करीब 234 थी। जिसमें 50 प्रतिशत पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते थे। लेकिन अब विभागीय ढांचे में इन पदों को समाप्त कर दिया है। उन्होंने जल्द से जल्द राज्य कर अधिकारियों के पदों को बहाल करने को कहा।

भवन मानचित्रों के लंबित प्रकरणों का जल्द समाधान करें

अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ जनता दरबार

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देशन पर जिला प्राधिकरण में लंबित, विचाराधीन भवनों के मानचित्रों के संबंध में अपर जिलाधिकारी ईला गिरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में लंबित भवनों के मानचित्रों को लेकर लोगों ने अपनी समस्याएं रखी।

बुधवार को आयोजित जनता दरबार में कई लोगों ने भवनों के मानचित्रों को लेकर अपनी-अपनी समस्याएं बताई। जिनका संज्ञान लेते हुए अपर जिलाधिकारी ने सहायक अभियंता जिला विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया कि जिन लोगों के लंबित प्रकरण हैं उनका निस्तारण समय पर करें।

: एडीएम इला गिरी जनता दरबार में अधिकारियों को निर्देश देते हुए।

उन्होंने मानचित्रकारों को भी निर्देशित किया भवनों का मानचित्र नियमानुसार बनाएं। जिससे लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

उन्होंने सहायक अभियंता जिला विकास प्राधिकरण को कहा कि जितने भी पिछले लंबित प्रकरण हैं उनका समाधान करें। इस दौरान सहायक अभियंता जिला विकास प्राधिकरण रणवीर सिंह, प्राधिकरण सहायक मनीष रावत प्राधिकरण टेक्निकल मुकेश टम्टा व मानचित्रकार व आवेदक उपस्थित थे।

चौधरी भागीरथी के अस्तित्व बचाने को करेगें आमरण अनशन

श्रीनगर गढ़वाल : किसान मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भोपाल चौधरी ने बुधवार को कहा कि भागीरथी नदी की दुर्दशा को देखते हुए वह आगामी 6 जुलाई से देवप्रयाग संगम तट पर आमरण अनशन करेंगे। कहा कि देवभूमि में बांधों के कारण मोक्षदायनी गंगा का अस्तित्व खतरें में पड़ गया है। कहा कि जिसका जीता जाता उदाहरण देवप्रयाग में मां भागीरथी आज 45 किमी. तक पूरी सूख चुकी है। उन्होंने सभी गंगाप्रेमी और पर्यावरण प्रेमी को मां गंगा के अस्तित्व को बचाने को आगे आने का आह्वान किया। बुधवार को श्रीनगर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए भोपाल चौधरी ने कहा कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीदारी मिलकर गंगा बनाती है, लेकिन आज टीएचडीसी बांध के कारण भागीरथी आज पूरी तरह से सुख चुकी है। जिससे देवप्रयाग में देश-विदेश से पहुंचने वाले श्रद्धालु भी मायूस होकर लौट रहे हैं। कहा कि भागीरथी में तमाम जलजीव भी तड़प कर मर गए हैं।

रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक हाईवे पर बंद रहेगी आवाजाही

वर्षाकाल में पहाड़ी से लगातार गिर रहे बोल्डर व मलबे को देखते हुए लिया गया निर्णय

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : वर्षाकाल में कोटद्वार-दुगड्डा के मध्य का सफर चुनौती बनता जा रहा है। हल्की बारिश में ही पहाड़ी से लगातार बोल्डर व मलबा गिर रहा है। जिसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात घंटों बाधित हो रहा। वर्षाकाल में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बंद रखने का निर्णय लिया है।

वर्षाकाल के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग से आवागमन करते वाहन

कोटद्वार-दुगड्डा के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर दस से अधिक डेंजर जोन बने हुए हैं। कई स्थानों पर पहाड़ी से लगातार बोल्डर गिर रहे हैं। तीन दिन पूर्व ही बरसाती रपटे के समीप पहाड़ी से गिर बोल्डर की चपेट में आने से एक मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जिसमें एक व्यक्ति की भी मौत हो गई थी। वहीं, आमसौड़ के समीप मलबा हटाने के दौरान सड़क पर खड़े एक ट्रक के ऊपर भी बोल्डर गिर गया था। दुर्घटना में ट्रक सवार व्यक्ति की मौत हो गई थी। पिछले तीन दिन से हल्की बारिश होने पर ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा व बोल्डर गिर रहा है। जिससे यातायात बाधित हो रहा है।

ऐसे में जिलाधिकारी ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल बरसात में रात के समय राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करने के निर्देश दिए है। कहा कि केवल एमरजेंसी वाहनों को ही राष्ट्रीय राजमार्ग से आवागमन करने की अनुमति होगी। उन्होंने पुलिस, प्रशासन व नगर निगम को भी वर्षाकाल में अलर्ट रहने के निर्देश दिए।

उत्तर रेलवे
आज़ादी का अमृत महोत्सव
ई–नीलामी
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक/कोचिंग, (ए.सी.ओ) उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल के द्वारा पे एंड यूज पार्किंग एवं एटीएम को IREPS के माध्यम से विभिन्न स्टेशनों पर ठेके पर देने हेतु ई– बोलियाँ www.ireps.gov.in पर दिनांक 13.07.2024 एवं 18.07.2024 को आमंत्रित की जायेगी, जिसकी विस्तृत जानकारी, नियम व शर्ते www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है।
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ 2008/24

उत्तर रेलवे
आज़ादी का अमृत महोत्सव
अनुबंध के आधार पर मेडिकल प्रैक्टिशनरों के लिए वॉक–इन–इंटरव्यू के संबंध में
मुरादाबाद मंडल पर 02 (01–यूआर और 01–एससी) कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स (जीडीएमओ) की नियुक्ति के लिए वॉक–इन–इंटरव्यू का विज्ञापन 07.08.2024 को मंडल रेलवे अस्पताल, मुरादाबाद में सुबह 11 बजे आयोजित किया जाना है। संबंधित जानकारी रेलवे की वेबसाइट www.Indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है।
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ 2005/24

उत्तर रेलवे
आज़ादी का अमृत महोत्सव
शुद्धिपत्र–1
इच्छा की अभिव्यक्ति
इस कार्यालय की निविदा सूचना संख्या No. NR-MB-OMED(INSP)/1/2024 dated 21/06/2024 जो कि दिनांक 25 जून, 2024 के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी, उसका संशोधित निविदा प्रपत्र वेबसाइट www.nr.indianrailway.gov.in पर अपलोड किया गया है। अतः कृपया संशोधित निविदा प्रपत्र को डाउनलोड करके अपनी ऑफर उसी पर प्रस्तुत करें।
सं.: NR-MB-OMED(INSP)/1/2024 दिनांक: 02/07/2024 2023/24
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

एक नजर

कुष्ठ पीड़ित दिव्यांगजनों के लिए नायाब पहल

देहरादून। दून के सीएमओ डॉ. संजय जैन ने कुष्ठ आश्रमों में रहने वाले कुष्ठ पीड़ित दिव्यांगजनों के लिए नायाब पहल की है। दिव्यांग प्रमाण पत्र का लाभ देने के लिए उन्हें चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्हें आश्रम लाने एवं छोड़कर आने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग उठाएगा। बुधवार को जिला कुष्ठ अधिकारी डॉ. सीएस रावत को व्यवस्था बनाने को निर्देशित किया। बुधवार को सीएमओ के निर्देश पर शांति कुष्ठ आश्रम, नवजीवन कुष्ठ आश्रम और रोटरी कुष्ठ आश्रम में विभागीय वाहन भेजकर छह दिव्यांग जनों को शिविर तक लाया गया और प्रमाण पत्र बनाने संबंधी प्रक्रिया पूरी कर वापस आश्रम ले जाया गया। डॉ. जैन ने कहा कि दिव्यांगजनों को लाभार्थीपरक सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ मिल सके, इसी प्रयास के तहत यह व्यवस्था की गई है।

सचिवालय सहायकों को तत्काल मिले एसीपी का लाभ

देहरादून। उत्तराखंड सचिवालय संघ ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में बुधवार को मुलाकात कर सचिवालय सहायकों को एसीपी का लाभ देने की मांग की। सीएम के समक्ष अपना पक्ष रखा। इसी के साथ संघ के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम की ओर से दिए गए सभी आश्वासनों के पूरा होने पर आभार जताया। सीएम का सम्मान समारोह आयोजित करने को समय मांगा। सचिवालय में मुलाकात के दौरान अध्यक्ष सुनील लखेड़ा ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में सीएम के समक्ष जो भी मांगे उठाई गई थी, वे सभी पूरी हो गई हैं। ये पहला मौका है, जब सरकार ने संघ के अनुरोध पर एक साथ सभी प्रमुख मांगों को पूरा कर दिया हो। अब कर्मचारियों को बिना वेतन कटौती के बाल्य देखभाल अवकाश का लाभ मिल रहा है। सचिवालय अधिकारी कर्मचारी कल्याण कोष के लिए 25 लाख रुपए जारी किए गए। 300 दिन का उपार्जित अवकाश अर्जित करने के बाद भी एक जनवरी और एक जुलाई को अर्जित अवकाश 31 दिसंबर तक कभी भी उपयोग करने की मंजूरी दी गई।

महासचिव राकेश जोशी ने कहा कि सचिवालय परिसर में पैथोलॉजी ब्लड कलेक्शन सेंटर की स्थापना की गई है। पार्किंग का निर्माण कराया जा रहा है। नए भवन का निर्माण को स्वीकृति दी गई। सचिवालय आवासीय कालोनी से सचिवालय तक ई बस सेवा शुरू की गई। इन तमाम मांगों के पूरा होने पर कर्मचारी मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं। इसके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली ने बताया कि सीएम के समक्ष सचिवालय सहायकों को एसीपी का लाभ देने की मांग रखी गई। आश्वासन दिया गया कि अगली कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा।

सचिवालय घेराव करेंगे राज्य कर कर्मचारी

देहरादून। राज्य कर कर्मचारी सोमवार को सचिवालय का घेराव करेंगे। पदों में हुई कटौती से नाराज कर्मचारियों ने बुधवार को राज्य कर मुख्यालय में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया। उत्तराखण्ड राज्य कर कर्मचारी संयुक्त मोर्चा पिछले तीन दिनों से कर कार्यालयों में धरना प्रदर्शन कर आंदोलन कर रहा है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने बताया कि विभागीय पुनर्गठन के दौरान राज्य कर कर्मचारियों के 243 पद समाप्त कर दिए गए हैं। कर्मचारियों ने इस संदर्भ में मुख्यालय व शासन के अफसरों से इस संदर्भ में सही जानकारी मांगी तो कोई भी इस संदर्भ में कुछ कहने को राजी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक विभाग के 243 पदों को बहाल नहीं कर दिया जाता उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य कर विभाग के सभी कर्मचारी सोमवार को सचिवालय का घेराव भी करेंगे। इधर बुधवार को भी कर्मचारियों ने अपने सभी कार्यालयों में धरना एवं प्रदर्शन किया। इस दौरान संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष जगमोहन नेगी, महासचिव अरविंद जोशी, भरत राणा, कैलाश बिष्ट, सुनील कुमार, विपिन डंगवाल, राजेन्द्र जोशी, नैन सिंह पंवार, दीपक शर्मा, अनुज जैन, भूपेन्द्र भंडारी, राकेश बिष्ट के साथ ही अनेक कर्मचारी मौजूद रहे।

हाथरस हादसे पर दुख जताया

देहरादून। हाथरस के रतिभानपुर में सत्संग के समापन पर मची भगदड़ में बड़ी संख्या में लोगों की मौत पर जमीयत उलेमा ए हिंद उत्तराखंड ने गहरा दुख जताया है। प्रदेश अध्यक्ष मौलाना हुसैन अहमद कासमी और प्रदेश महामंत्री मौलाना शराफत कासमी ने कहा कि यह हादसा अत्यंत हृदय विदारक है। हादसे में 122 लोगों ने जान गंवाई है। जमीयत दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिजनों के साथ खड़ी है।

महाराज ने की यूपी के सीएम योगी से शिष्टाचार भेंट

जयन्त प्रतिनिधि। देहरादून : प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रदेश के पर्यटन, ग्रामीण निर्माण, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, धर्मस्व, संस्कृति एवं जलागम मंत्री सतपाल महाराज ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बीच सड़क, सिंचाई, पर्यटन, पंचायत और संस्कृति से संबंधित अनेक विषयों पर चर्चा करने के साथ-साथ आपसी सहयोग की भी बात कही।

मिनी ट्यूबवेल से जलापूर्ति होने से ग्रामीणों को मिली राहत

नई टिहरी : एक जून को टिहरी बांध से भागीरथी का जल रोके जाने के बाद यहां मुनेठ सजवाण कांडा पंपिंग योजना से जुड़ी दस ग्राम पंचायतों की जलापूर्ति भी ठप पड़ गयी थी। जल संस्थान की ओर से भागीरथी में पोखर बनाकर पाइपों के जरिये मुख्य टैंक तक पानी पहुंचाया गया। मगर इससे पर्याप्त जलापूर्ति गांवों के लिए नहीं हो पा रही थी। टीएचडीसी की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था बनाने को लेकर यहां जल संस्थान को सहयोग दिया गया। जिसमें योजना के मुख्य टैंक के निकट डीप बोरिंग की गयी, मगर उसमें पानी नही निकल पाया। जिसके बाद तीन किमी. दूर राजमार्ग स्थित भुईट गधेरे से करीब डेढ़ सौ मीटर बोरिंग कर पानी निकाला गया। यहां मिनी ट्यूबवेल स्थापित कर तीन इंच पानी बीते सोमवार को मुख्य टैंक तक पहुंचाया गया। (एजेंसी)

बारिश में भी धरने पर डटे रहे छात्र

श्रीनगर गढ़वाल : गढ़वाल केन्द्रीय विवि में बुधवार को नियुक्तियों में हो रही गड़बड़ियों, विवि द्वारा फीस वृद्धि किए जाने, पीएचडी प्रवेश परीक्षा में कथित धांधली के विरोध को लेकर छात्रों का धरना जारी है। बारिश के बावजूद भी विवि के प्रशासनिक भवन के मुख्य गेट पर छात्र धरने में डटे रहें। छात्रों ने मांगें पूरी होने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है।

गढ़वाल विवि के छात्रसंघ अध्यक्ष सुधांशु थपलियाल ने कहा कि विवि द्वारा छात्रों की फीस में वृद्धि की जा रही है। जिसके चलते पहाड़ के गरीब घरों के छात्रों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कहा विवि प्रशासन छात्रों की फीस में वृद्धि कर छात्रों के शिक्षा के अधिकारों का हनन कर रहा है। आरोप लगाया कि प्रति कुलपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी उन्हें पद पर बने रहने दिया जा रहा, जोकि नियम विरुद्ध है। कहा कि विवि में दो नई बसें आ गई हैं। लेकिन उनका संचालन नहीं किया जा रहा है। इस कारण विवि के चौरास परिसर से बिड़ला परिसर तक छात्रों को पैदल ही आना पड़ रहा है। विवि के पास कुल चार बसें हैं। जिनमें से केवल दो ही बसें संचालित हो रही हैं। उन्होंने विवि प्रशासन से जल्द से जल्द विवि के प्रतिकुलपति को पद से हटाने, फीस में वृद्धि न किए जाने, दो नई बसों का संचालन करने, पीएचडी प्रवेश परीक्षा की जांच करने की मांग की। आर्यन छात्र संगठन से जुड़े छात्र नेता नीरज पंचोली ने कहा कि छात्रों की फीस में वृद्धि कर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कहा कि अगर विवि प्रशासन छात्रों के हितों में फैसला नहीं लेता है तो छात्र उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मौके पर कैवल्य जखमोला, आकाश रतूड़ी आदि मौजूद रहें। इधर फीस वृद्धि मामले पर अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. एसएस नेगी ने कहा कि केवल प्रथम सेमेस्टर के छात्रों की फीस में वृद्धि की गई हैं। कहा फीस में 10 से 15 फीसदी तक वृद्धि की गई है जो कि बहुत कम है। (एजेंसी)

सड़क पर आया मलबा, यातायात हुआ बाधित

रुद्रप्रयाग : मन्दाकिनी घाटी में बुधवार सुबह हुई चार घंटे की भारी बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव और भूस्खलन की घटनाएं हुई। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में अगस्त्यमुनि के सौड़ी के खेतों का मलबा सड़क पर आने से पौन घंटे तक यातायात बाधित रहा। इस कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बाद में यात्रियों ने मलबा साफ कर यातायात को सुचारु किया। अगस्त्यमुनि नगर क्षेत्र में जवाहरनगर वार्ड में डिग्री कॉलेज के समीप सड़क जलभराव होने से तलाब में तब्दील हो गई। यही हाल पुरानादेवल में भी दिखा।

बादल फटने से स्कूल के रास्तों व खेतों में आया मलवा

जयन्त प्रतिनिधि।

रूद्रप्रयाग : जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि बुधवार को समय प्रातः 8 बजे ग्राम प्रधान रुमसी द्वारा सूचना दी गई कि रुमसी देवीदार तोक में बादल फटने के कारण स्कूल का रास्ता व कुछ खेतों में मलवा आया है।

घटना की सूचना प्राप्त होते ही मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जीएस खाती, मुख्य कृषि अधिकारी लोकेंद्र सिंह बिष्ट, खंड विकास अधिकारी अगस्त्यमुनि प्रवीन भट्ट एवं जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार तथा राजस्व उप निरीक्षक घटना स्थल के लिए रवाना हुए। घटना स्थल पर पाया कि देवधार में जूनियर हाईस्कूल का रास्ता एवं कतिपय कृषि भूमि का आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस घटना में किसी प्रकार से कोई जानमाल, जनहानि एवं पशु हानि नहीं हुई है। घटनास्थल पर पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जीएस खाती ने मुख्य कृषि अधिकारी, राजस्व उप निरीक्षक एवं खंड विकास अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आंशिक रूप से क्षति हुई कृषि भूमि एवं जूनियर हाईस्कूल रास्ते का आंगणन प्रस्ताव आपदा प्रबंधन के तहत तैयार कर शीघ्रता से शीघ्र उपलब्ध कराने, जूनियर हाईस्कूल के रास्ते में आए मलबे को तत्परता से हटाने निर्देश दिए हैं।

बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग

नई टिहरी : जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव बुडोगी के लोगों ने बुधवार को डीएम मयूर दीक्षित को ज्ञापन सौंपकर बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग उठाई। कहा कि गांव में बंदरों को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए जाएं।

ग्राम बुडोगी की महिलाओं में सुशीला, मीना, गुड्डी और भूपेंद्र चौहान ने डीएम को सौंपे ज्ञापन में बताया कि गांव में बंदरों का इतना आतंक हो गया है कि छोटे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी बंदरों के आतंक का भय निरंतर बना हुआ है। गांव के निकटस्थ क्षेत्रों में बंदरों और लंगूरों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। बंदर फसलों और घरों को भी सीधा नुकसान पहुंचा रहे हैं। बंदरों के आतंक से लगातार बड़ी दुर्घटना होने की आशंका निरंतर बनी हुई है।

अतिवृष्टि से आम जन जीवन अस्त व्यस्त

रुद्रप्रयाग : अगस्त्यमुनि के समीपवर्ती क्षेत्र रुमसी में बुधवार को अतिवृष्टि से जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के आवाजाही और स्कूल के रास्तों में मलबा आया है। जिससे आवाजाही में मुश्किलें हो रही है। अतिवृष्टि की सूचना मिलते ही प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि बुधवार सुबह ग्राम प्रधान रुमसी द्वारा सूचना दी गई कि रुमसी देवीदार तोक में मूसलाधार बारिश के कारण स्कूल का रास्ते और कुछ खेतों में मलबा आ गया है। घटना की सूचना प्राप्त होते ही मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जीएस खाती, मुख्य कृषि अधिकारी लोकेंद्र सिंह बिष्ट, खंड विकास अधिकारी अगस्त्यमुनि प्रवीन भट्ट एवं जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार के साथ ही राजस्व उप निरीक्षक घटनास्थल को रवाना हुए। घटनास्थल पर देवधार में जूनियर हाईस्कूल का रास्ता एवं कई लोगों की कृषि भूमि को आंशिक रूप से क्षति हुई है। इस घटना में किसी प्रकार से कोई जानमाल, जनहानि एवं पशु हानि नहीं हुई है। घटनास्थल पर पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जीएस खाती ने मुख्य कृषि अधिकारी, राजस्व उप निरीक्षक एवं खंड विकास अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आंशिक रूप से क्षति हुई कृषि भूमि एवं जूनियर हाईस्कूल रास्ते का आंगणन प्रस्ताव आपदा प्रबंधन के तहत तैयार कर शीघ्रता से शीघ्र उपलब्ध कराया जाए।

आज छोड़ा जाएगा जल विद्युत परियोजना से पानी

रुद्रप्रयाग : मंदाकिनी नदी पर बनी सिंगोली-भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना से गुरुवार को बैराज के सभी गेटों से पानी छोड़ा जाएगा। जिससे नदी का जल स्तर बढ़ना तय है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि सिंगोली भटवाड़ी जल परियोजना प्रबंधन द्वारा जानकारी दी गई कि बैराज से सभी गेटों से गुरुवार को पानी छोड़ा जाएगा। नदी किनारे रहने वाले लोग सतर्क रहें साथ ही कोई भी नदी किनारे न जाएं। उन्होंने बताया कि कंपनी के अनुसार गुरुवार 4 जुलाई को सिंगोली भटवारी जल विद्युत परियोजना के कुंड बैराज से सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक सभी गेटों से पानी छोड़ा जाएगा। सिल्ट फ्लैशिंग के लिए ऐसा किया जाना अति आवश्यक है। जिस वजह से मंदाकिनी नदी का जल स्तर एवं जल प्रवाह और अधिक बढ़ेगा। उन्होंने नदी के आसपास रह रहे लोगों को इसकी जानकारी देते हुए सचेत किया है। वे लोग नहीं तो स्वयं नदी किनारे जाएं और न ही अपने मवेशियों को नदी की ओर जाने दें। ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। (एजेंसी)

12 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए

नई टिहरी : वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी शारदा शर्मा ने बताया कि चंबा में निरीक्षण किया गया। संदेह के आधार पर दूध, नमक, आटा, मैदा, सूजी, चीनी, चावल, अरहर दाल, सेंवई, बूंदी, नमकीन आदि के 12 सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गये हैं। लैब की रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान एक्सपायरी सात पैकेट दलिया और एक पैकेट बूंदी मौके पर नष्ट किए गए। खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर चार कारोबारियों को नोटिस जारी किया गया। (एजेंसी)

नवनियुक्त थानाध्यक्ष ने संभाला कार्यभार

नई टिहरी : थत्यूड़ के नवनियुक्त थानाध्यक्ष अमित शर्मा ने मंगलवार शाम को कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने अपराध नियंत्रण, नशा और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाने और आम जन की सुरक्षा के लिए कार्य करना अपनी प्राथमिकता बताई। कहा कि थत्यूड़ क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था चुनौती बनी हुई है। जिसे व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ठीक किया जाएगा। पत्रकार वार्ता करते हुए एसएचओ शर्मा ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध पर नियंत्रण के लिए वह पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

मानसून सीजन को देखते हुए क्षेत्र में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में नियमित रूप से निगरानी की जाएगी। आमजन और व्यापारियों को भरोसा दिया कि उनकी समस्या का समय रहते निस्तारण किया जाएगा। थत्यूड़ पुलिस मित्रता के स्लोगन को प्रदर्शित भी करेगी।

डायरिया से बचाव के लिए घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करें : डीएम

चमोली : सघन डायरिया नियंत्रण पखवाडा के प्रभावी क्रियान्वयन, परिवार नियोजन और 15वें वित्त आयोग की संस्तुति पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उपकेद्रों को उपकरण एवं सामग्री वितरण हेतु बुधवार को जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समन्वय समिति की बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डायरिया से बचाव के लिए घर-घर जाकर लोगों को जागरूक किया जाए। आशा के माध्यम से शून्य से 05 साल के बच्चों को ओआरएस और जिंक टेबलेट उपलब्ध कराई जाए। विद्यालयों में विशेष फोकस करते हुए डायरिया से बचाव तथा रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। साथ ही सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। ताकि संचारी रोगों से लोगों को बचाया जा सके। स्वास्थ्य उपकरणों के वितरण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केद्रों के चयन हेतु जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि दूरस्थ क्षेत्र के स्वास्थ्य उपक्रेदों को प्राथमिकता पर रखते हुए स्वास्थ्य उपकरणों का वितरण किया जाए। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत 11 से 24 जुलाई तक आयोजित होने वाले जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा का प्रचार प्रसार किया जाए। प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अभिषेक गुप्ता ने बताया कि डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम 01 जुलाई से 31 अगस्त तक चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में 30916 बच्चों को ओआरएस और जिंक टेबलेट वितरण का लक्ष्य रखा गया है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत 11 से 24 जुलाई तक नसबंदी शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जिसमें 11 जुलाई को दशोली व गैरसैंण, 12 जुलाई को कर्णप्रयाग, 13 जुलाई को थराली, 15 जुलाई को जोशीमठ, 18 जुलाई को देवाल, 19 जुलाई को पोखरी, 20 जुलाई को कर्णप्रयाग, 22 जुलाई को नारायणबगड़, 23 जुलाई को घाट और 24 जुलाई को जिला चिकित्सालय में नसबंदी शिविर लगाए जाएंगे।

बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण सबकी जिम्मेदारी : विनोद कपरवाण

चमोली : उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग के सदस्य विनोद कपरवाण की अध्यक्षता में बाल तस्करी से आजादी 2.0 अभियान को लेकर बार संघ के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बाल तस्करी, चाइल्ड हेल्पलाइन, खोए हुए बच्चों व निराश्रित बच्चों की शिक्षा पर विस्तृत चर्चा की गयी।

उन्होंने कहा कि बाल तस्करी एक गंभीर समस्या है बच्चे देश का भविष्य है। उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। समाज में चेतना जगाने के लिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने बाल तस्करी से आजादी अभियान चलाया है। जिसमें प्रदेश के 7 जिलों को चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि चमोली जनपद बाल तस्करी, बाल श्रम से मुक्त हो इसके लिए जनपद के जागरूक नागरिक व जनप्रतिनिधि सभी प्रयासरत रहें। बाल तस्करी रोकने के लिए अभिभावकों और समाज को सजग व जागरूक रहने की आवश्यकता है। उन्होंने बाल तस्करी, किशोर न्याय के लिए पुलिस व अन्य संबंधित विभागों को समन्वय के साथ काम करें। कहा कि कहीं भी बाल तस्करी या बाल शोषण, बाल श्रम व बाल विवाह, बच्चों के खोने, घर नहीं आने संबंधी आदि स्थितियों में चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098 पर सम्पर्क करें। इस दौरान श्रम अधिकारी के न होने पर भी नाराजगी जताई। इस दौरान पीडी आनन्द सिंह,सीओ अमित सैनी, डीएसडीओ धनंजय लिंगवाल हिमाद संस्था के उमाशंकर बिष्ट सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। (एजेंसी)

क्षतिग्रस्त रिठोला-बिनोला पुलिया दे रहा दुर्घटना को न्योता

चमोली : गैरसैंण विकासखंड के न्याय पंचायत देवलकोट के पंय्या गांव में रिठोला-बिनोला गधेर में बनाई गई पैदल पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। इससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है।

पूर्व जिला पंचायत सदस्य और पूर्व प्रधान ग्राम पंय्या कलम कोहली का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में ब्लॉक कार्यालय को अवगत कराया, लेकिन काम नहीं हुआ। बताया कि पैदल पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण राइंका देवलकोट में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को भी आने जाने में परेशानी हो रही है। (एजेंसी)

उत्तराखंड को कोयला आपूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यूजेवीएन लिमिटेड एवं टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम को कोयला आधारित तापीय बिजली संयंत्र की स्थापना हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा शक्ति नीति के अंतर्गत अप्रैल 2024 में कोयला आवंटन हेतु भारत सरकार को अवगत कराया गया कि राज्य सरकार अपने सार्वजनिक उपक्रम यूजेवीएन लिमिटेड के अतिरिक्त टीएचडीसी एवं यूजेवीएन लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम के माध्यम से भी कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना की इच्छुक है। इसी क्रम में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा भी उत्तराखंड राज्य को शक्ति नीति के अंतर्गत 1320 मेगावाट तापीय विद्युत उत्पादन के प्रयोजनार्थ कोयला आपूर्ति हेतु प्रबल संस्तुति की गई थी। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार द्वारा टीएचडीसी तथा यूजेवीएन लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम के माध्यम से तापीय विद्युत संयंत्र स्थापना पर सहमति जताई गई।

शक्ति नीति के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड केंद्र एवं राज्य सरकारों की उत्पादन कंपनियों तथा उनके संयुक्त उपक्रमों को अधिसूचित दरों पर कोयला आपूर्ति की अनुमति दे सकती है।

समस्त विभागीय भूमि एवं परिसंपत्तियों का डिजिटल लैंड बैंक जल्द होगा तैयार : डीएम

चमोली : जिले में सरकारी भूमि-परिसंपत्तियों का डिजिटल लैंड बैंक बनाने और विभागीय परिसंपत्तियों को उचित उपयोग हेतु किराए पर दिए जाने को लेकर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बुधवार को समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देशित किया कि समस्त विभागीय भूमि एवं परिसंपत्तियों का डिजिटल लैंड बैंक शीघ्र तैयार किया जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि लैंड बैंक के माध्यम से भविष्य में सरकारी भूमि का उपयोग उचित योजना के साथ बुनियादी सुविधाओं की स्थापना हेतु किया जाएगा। विभागों के पास समस्त आवासीय, अनावासीय, खाली भूमि या अन्य किसी भी प्रकार की भूमि जिस पर विभाग का आंशिक या पूर्ण कब्जा हो, उसका सटीक डिजिटल लैंड बैंक तैयार किया जाए। सभी विभाग अपनी परिसंपत्तियों को पोर्टल पर दर्ज करें। कोई भी परिसंपत्ति छूटनी नही चाहिए। ताकि भविष्य में अतिक्रमण को रोका जा सके और विकास योजनाओं के लिए सरल और सुगम तरीके से सरकारी भूमि उपलब्ध हो सके। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसी भूमि-परिसंपत्तियां जो विभागीय उपयोग में नही है, लेकिन आम जनता के लिए किसी विशेष उद्देश्य से उपयोगी है, उनको चिन्हित कर प्रचार प्रसार करें और विभागीय उपयोग के उपरांत खाली संपत्तियों को आम नागरिकों के उचित उपयोग हेतु किराए पर दिया जाए। इससे विभाग की परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग के साथ राजस्व भी प्राप्त होगा। जिसका 25 प्रतिशत तक विभाग अपनी परिसंपत्तियों के रखरखाव पर खर्च कर सकते है।

उन्होंने कहा कि आगे से जिला योजना और अन्य मदों से विभागीय परिसंपत्तियों के रख रखाव हेतु फंड जारी करते समय इसको भी देखा जाएगा कि विभागों ने अपनी परिसंपत्तियों को किराए पर देकर कितनी आय अर्जित की है। उन्होंने निर्देश दिए कि परिसंपत्तियों से आय अर्जित करने हेतु सभी विभागों का न्यूनतम लक्ष्य भी निर्धारित किया जाए। ताकि समय समय पर इसका आंकलन भी किया जा सके। अपर जिलाधिकारी ने बैठक में बताया कि जनपद में अब तक 76 प्रतिशत सरकारी भूमि-परिसंपत्तियों का डिजिटल लैंड बैंक तैयार कर लिया गया है। जनपद के सभी विभागों के पास दर्ज 11682 परिसंपत्तियों में से 8956 परिसंपत्तियों का डिजिटल बाउंड्री बन चुकी है और जल्द ही शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, पीडी आनंद सिंह, सीओ पुलिस अमित कुमार सैनी, एसीएमओ डॉ. एमएस खाती, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक धर्म सिंह, समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं तहसीलों से सभी एसडीएम वर्चुअल माध्यम से उपस्थित थे। (एजेंसी)

जयन्त

संस्थापक
नरेन्द्र उनियाल
स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक और
सम्पादक
नागेन्द्र उनियाल
द्वारा जयन्त प्रकाशन डिग्री कॉलेज रोड, जौनपुर कोटद्वार गढ़वाल (उत्तराखण्ड) से मुद्रित तथा जयन्त कार्यालय चन्द्रसिंह गढ़वाली मार्ग, गैरसैंण, जनपद चमोली उत्तराखण्ड से प्रकाशित
RNI No.UTTHIN/2005/16338